04 - बीमार झीलों को बचाने के लिए नीति और नियत

05 - अभिव्यक्ति के खतरे उठाने के लिए प्रतिबद्ध हों

A Daily News Magazine

भोपाल

मंगलवार, 8 अप्रैल, 2025

06 - करो की वसूली को लेकर नपा का अभियान रहा सुस्त...

07 - मध्यप्रदेश में 4 लाख 87 हजार पद खाली, बेरोजगारों का इंतजार

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 22, अंक 208, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

वक्फ बोर्ड की धारा 40 को हटाना बहुत जरूरी सुधार है

आमना बेगम

वक्फ की ज़मीन को अक्सर अल्लाह की संपत्ति कहकर पुकारा जाता है- जिसका उद्देश्य उच्च उद्देश्य की पूर्ति करना और व्यावहारिक रूप से लोगों की सेवा करना है। यही वह सिद्धांत है जिस पर यह टिका हुआ है, लेकिन एक बार जब किसी पवित्र ट्रस्ट को इंसानी हाथों में छोड़ दिया जाता है, तो यह मानवीय दोषों के अधीन हो जाता है। भारत में वक्फ बोर्डों की कहानी जाने-माने पैटर्न पर चलती है। समुदाय की सेवा के इरादे से दान की गई ज़मीन- चाहे वह शिक्षा के ज़रिए हो, मस्जिदों को बनाए रखने के लिए, कब्रिस्तान के लिए ज़मीन देने या आर्थिक रूप से वंचितों की सहायता करने के लिए- अक्सर भ्रष्टाचार, खराब शासन और प्रणालीगत विफलता के मामले के रूप में समाप्त हो गई है।

व्यवहार में, वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन बड़े पैमाने पर अशरफ मुस्लिम (अभिजात वर्ग) के हाथों में रहा है, जिसमें व्यापक समुदाय का न के बराबर या कहे कि प्रतिनिधित्व ही नहीं है। सैद्धांतिक रूप में, वक्फ को राज्य कल्याण योजनाओं पर गरीब मुसलमानों की निर्भरता कम करनी चाहिए थी- फिर भी, कई लोग बुनियादी ज़रूरतों के लिए पूरी तरह से राज्य पर निर्भर हैं।

भारत में मुसलमानों की स्थिति की जांच करने के लिए तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा 2005 में गठित सच्चर समिति ने इस फर्क को जाना। 2006 में पेश इसकी रिपोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वक्फ बोर्डों द्वारा उत्पन्न राजस्व उनके नियंत्रण में विशाल संपत्तियों की तुलना में अनुपातहीन रूप से कम था। समिति ने अनुमान लगाया कि उचित सुधारों और कुशल उपयोग के साथ, वक्फ ज़मीन संभावित रूप से सालाना 12 हजार करोड़ रुपये उत्पन्न कर सकती है- एक चौंका देने वाली संख्या, खासकर वर्तमान अनुमानित राजस्व केवल 200 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की तुलना में हो। यह फर्क न केवल कुप्रबंधन का संकेत देता है, बल्कि यह अवास्तविक संभावनाओं की ओर भी इशारा करता है, एक ऐसी प्रणाली जो स्कूलों, समुदाय और घरों का समर्थन कर सकती थी, लेकिन प्रशासनिक उपेक्षा में फंसी हुई है।

वक्फ अधिनियम 1995 के तहत, अतिक्रमणों से धारा 54 के तहत निपटा जाना था, जिसमें वक्फ ज़मीन से अवैध कब्जाधारियों को हटाने के लिए कानूनी प्रक्रियाएं निर्धारित की गई थीं। हालांकि, सच्चर समिति की रिपोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि न केवल वक्फ संपत्तियों से राजस्व सृजन चिंताजनक रूप से कम था, बल्कि अतिक्रमण एक सतत और बढ़ती चुनौती थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कम से कम 58 हजार 889 वक्फ संपत्तियां अतिक्रमण का सामना कर रही हैं और 13 हजार से अधिक मुकदमेबाजी में उलझी हुई हैं। यह संख्याएं एक ऐसी प्रणाली के बारे में बहुत कुछ बताती हैं जो समुदाय की सेवा के लिए बनाई गई थी, लेकिन अक्सर अपनी नींव की रक्षा करने में विफल रही है।

हालांकि, सबसे ज़्यादा चर्चित कानून वक्फ अधिनियम की धारा 40 थी, जिसने वक्फ बोर्डों को संपत्तियों को वक्फ के रूप में पहचानने और घोषित करने का अधिकार दिया, भले ही उन्हें आधिकारिक तौर पर इस तरह दर्ज न किया गया हो। इसका इस्तेमाल विवादित या खराब दस्तावेज़ वाली ज़मीन पर स्वामित्व जताने के लिए किया गया।

वर्तमान वक्फ सुधार बहस धारा 40 के इर्द-गिर्द घूमती दिखती है, जो चुपचाप वक्फ अधिनियम का सबसे विवादित हिस्सा बन गई है। धारा 40 के तहत, वक्फ बोर्ड को यह निर्धारित करने के लिए स्वप्रेरणा से जांच शुरू करने का अधिकार है कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं- यह शक्ति केवल उसे ही प्राप्त है, तथा अन्य समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी अन्य धर्मार्थ या धार्मिक बोर्ड को नहीं दी गई है। धारा-40 के बचाव में तर्क वजनदार नहीं है। कई वक्फ संपत्तियां अनौपचारिक रूप से उपहार में दी गई थीं, सामुदायिक रूप से इस्तेमाल की गई थीं, या बस कभी भी उनका दस्तावेजीकरण नहीं किया गया था- खासकर औपनिवेशिक काल के दौरान जब रिकॉर्ड अक्सर अपूर्ण या अस्तित्वहीन होते थे। धारा 40 का उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना था, जो अन्यथा खो जाने या चुपचाप कब्जा लिए जाने की संभावना को सुरक्षित रखने का एक तरीका था। लेकिन यहीं से तनाव दिखना शुरू होता है। वक्फ बोर्ड एक अदालत नहीं है और फिर भी उसे एक गंभीर घोषणा करने की अनुमति है- जो संपत्ति की कानूनी स्थिति को प्रभावित करती है। हां, फैसले को चुनौती दी जा सकती है, लेकिन हाई कोर्ट में लड़ाई को ले जाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से दूसरे पक्ष पर आती है- अक्सर ऐसे व्यक्ति जिनके पास बहुत कम संसाधन या जागरूकता होती है।

धारा 40 को और भी अलग बनाने वाली बात यह है कि भारत में किसी भी अन्य धार्मिक संस्था को- चाहे वह हिंदू हो, ईसाई हो या सिख- किसी भी संपत्ति को अपने धार्मिक ट्रस्ट का हिस्सा घोषित करने का वैधानिक अधिकार नहीं है। यह स्वाभाविक रूप से एक बड़ा सवाल उठाता है- कानून के समक्ष समानता के बारे में।

धार्मिक दान संस्था को इतना शक्तिशाली उपकरण सौंपना कोई छोटी बात नहीं है और जबकि शक्ति अच्छे इरादे से सौंपी जाती है, यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। जब सावधानी से लागू किया जाता है, तो धारा 40 वह कर सकती है जिसके लिए इसका उद्देश्य था- ऐसी संपत्तियों की रक्षा करना जो अन्यथा समुदाय की पहुंच से दूर जा सकती है, लेकिन जब लापरवाही से या इससे भी बदतर, राजनीतिक रूप से उपयोग किया जाता है, तो यह बहुत अनुचित लगने लगता है।

और यही चिंता का विषय है। इस शक्ति का दुरुपयोग न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई मजबूत व्यवस्था नहीं दिखती। मेरे हिसाब से, धारा 40 को हटाना वक्फ पर हमला नहीं है, बल्कि एक ज़रूरी सुधार है। अनावश्यक शक्ति को हटाना किसी संस्था को कमजोर करने के समान नहीं है; कभी-कभी, इसे वापस उद्देश्य पर लाने का यही एकमात्र तरीका होता है। अब ध्यान बेहतर प्रबंधन, अधिक पारदर्शिता और एक ऐसी प्रणाली पर होना चाहिए जो वास्तव में उस समुदाय की सेवा करे जिसके लिए इसे बनाया गया था। संस्थाओं, शासन और इस विचार में भरोसा कि समुदाय के कल्याण के लिए बनाई गई कोई चीज़ अभी भी उस उद्देश्य को पूरा कर सकती है। धारा-40 भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन असली इम्तेहान अभी बाकी है। क्या ये सुधार पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन लाएंगे या सिर्फ गहरे संरचनात्मक मुद्दों को संबोधित किए बिना सत्ता को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करेंगे?

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

बाजार पर भारी पड़ा 'ट्रंप टैरिफ'

- **सेंसेक्स 2227 अंक टूटा, निफ्टी 22000 से नीचे फिसला, 19 लाख करोड़ डूबे**

नईदिल्ली (एजेंसी)। सोमवार, 7 अप्रैल को शेयर मार्केट में साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट आई। इसके कारण निवेशकों के करीब 19 लाख करोड़ रुपए डूब गए। जापान, हॉन्गकॉन्ग समेत अन्य एशियाई बाजारों में भी बड़ी गिरावट देखी गई है। ऐसे में इस दिन को 'ब्लैक मंडे' कहा जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह ट्रम्प का रेसिप्रोकल टैरिफ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 के आखिर तक अमेरिका में आर्थिक मंदी आ सकती है।

अमेरिकी एक्सपर्ट बोले- 1987 जैसा होगा हाल- फाइनेंशियल कॉमेंटेटर और सीएलबीसी के शो मैड मनी के होस्ट जिम क्रैमर की चेतावनी के बाद भारतीय बाजार 4 प्रतिशत गिरकर कारोबार कर रहे हैं। क्रेमर ने दो दिन पहले कहा था कि अमेरिकी बाजार में 1987 जैसा 'ब्लैक मंडे' आ सकता है। क्रेमर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ओर से दुनियाभर के देशों पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को इसकी वजह बताया है। क्रेमर ने कहा- अगर ट्रम्प नियमों का पालन करने वाले देशों को राहत नहीं देते हैं, तो 1987 जैसे हालात बन सकते हैं। तब तीन दिन की गिरावट के बाद सोमवार को बाजार 22 प्रतिशत गिर गया था।

आज भारतीय बाजार का इंडेक्स सेंसेक्स 3000 अंक (4 प्रतिशत) गिरकर करीब 72,300 के स्तर पर है। निफ्टी में 900 अंक (4.50 प्रतिशत) की गिरावट है। ये 22,000 से नीचे कारोबार कर रहा था।

सुप्रभात

गो ज़रा सी बात पर बरसों के याराने गए
लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए

गर्मी-ए-महफ़िल फ़क़त इक
नारा-ए-मस्ताना है
और वो खुश हैं कि इस महफ़िल से दीवाने गए

मैं इसे शोहरत कहूँ या अपनी रुस्वाई कहूँ
मुझ से पहले उस गली में मेरे अफ़साने गए

वहशतें कुछ इस तरह अपना मुक़द्दर बन गईं
हम जहाँ पहुँचे हमारे साथ वीराने गए

यूँ तो वो मेरी रग-ए-जाँ से भी थे नज़दीक-तर
आँसुओं की धुँध में लेकिन न पहचाने गए

अब भी उन यादों की खुश्बू ज़ेहन में महफ़ूज़ है
बार-हा हम जिन से गुलज़ारों को महकाने गए

क्या क़यामत है कि 'ख़ातिर'
कुश्ता-ए-शब थे भी हम
सुब्ह भी आई तो मुजरिम हम ही गर्दाने गए।

- ख़ातिर ग़ज़नवी

काबिल टीचर्स के लिए कोर्ट का फैसला अन्यायपूर्ण : ममता

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को उन शिक्षकों और स्टाफर्स से मुलाकात की, जिनकी भर्ती सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश से बंधे हुए हैं। यह फैसला उन कैंडिडेट्स के लिए अन्याय है, जो काबिल शिक्षक थे।

ममता ने यह मुलाकात कोलकाता के नेताजी इनडोर स्टेडियम में की। इस दौरान उन्होंने कहा, आप लोग यह मत समझिए कि हमने फैसले को स्वीकार कर लिया है। हम पत्थरदिल नहीं हैं। मुझे ऐसा कहने के लिए जेल भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है। वहीं, शिक्षकों ने कहा कि घोटाले में सीएम,उनका मंत्रिमंडल और आयोग सभी शामिल हैं। नौकरियों के बदले रिश्वत ली गई है।

वर्ल्ड हेल्थ डे पर - पीएम मोदी ने दिया

आरोग्यम परमं भाग्यम' का संदेश

- कहा- अच्छा स्वास्थ्य समृद्ध समाज की नींव रखता है
- मोटापे को लेकर जताई चिंता, दी सलाह, फिट रहने के लिए तेल का प्रयोग करें कम

नई दिल्ली (एजेंसी)। 'आरोग्यम परमं भाग्यम' यानी सेहतमंद होना परम सौभाग्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड हेल्थ डे के अवसर पर इस श्लोक के माध्यम से स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। उन्होंने कहा, 'विश्व स्वास्थ्य दिवस के इस मौके पर, हम एक स्वस्थ दुनिया के निर्माण की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से संकल्पित करें।'

मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र पर निरंतर ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा, 'हम हेल्थ सैक्टर में निवेश करेंगे, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य से ही समृद्ध समाज की नींव रखी जा सकती है।

जीवनशैली में बदलाव ने भारतीयों के स्वास्थ्य को चुनौती दी

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने मोटापे की बढ़ती समस्या पर चिंता व्यक्त की और लोगों से अपने खाने में तेल का इस्तेमाल 10 प्रतिशत तक कम करने की अपील की।

उन्होंने स्वास्थ्य को सबसे बड़ी पूंजी और भाग्य बताते हुए कहा, 'जीवनशैली में बदलाव ने भारतीयों के स्वास्थ्य को चुनौती दी है, और मोटापे की समस्या एक गंभीर खतरे के रूप में उभरी है।

प्रधानमंत्री ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 2050 तक भारत में 440 मिलियन से अधिक लोग मोटापे से प्रभावित होंगे।'

प्रधानमंत्री मोदी ने व्यायाम को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाने पर भी जोर दिया।

- संघ प्रमुख भागवत बोले

औरंगजेब को न मानने वालों का संघ में स्वागत

कहा-भारतीयों की पूजा पद्धति अलग, संस्कृति एक, काशी से दिए 4 बड़े मैसेज

वाराणसी (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने काशी में कहा-औरंगजेब को आदर्श न मानने वाले भारतीयों का संघ में स्वागत है। शाखा में शामिल होने वाले सभी लोग भारत माता की जय बोलें और भगवा ध्वज के प्रति सम्मान प्रकट करें। उन्होंने कहा- भारतीयों का रहन-सहन, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन संस्कृति एक है। भागवत मलदहिया में संघ की शाखा में शामिल हुए। वहां स्वयं सेवकों के सवालों के जवाब दिए।

इससे पहले, 30 मार्च को नागपुर में पीएम मोदी ने भागवत से मुलाकात की थी। अपनी 5 दिवसीय काशी यात्रा में भागवत ने हिंदुत्व पर संदेश दिया। कहा- हिंदू समाज के सभी पंथ, जाति, समुदाय साथ आएं। श्मशान, मंदिर और पानी सब हिंदुओं के लिए एक होना चाहिए। इसमें भेदभाव क्यों ?

भागवत ने 4 बड़े मैसेज दिए। पहला- हिंदू जातियों में नहीं बंटना चाहिए। दूसरा- गांवों में संघ की गतिविधियां बढ़ेंगी। तीसरा- गांव से लेकर शहर तक पढ़े-लिखे युवाओं को संघ से जोड़ा जाएगा। चौथा- 2027 से पहले भाजपा और संघ एक होगा। काशी के बाद 7 अप्रैल को मोहन भागवत लखनऊ में थे, आज 8 अप्रैल को कानपुर जाएंगे। यहां भी जातियों में बंटे समाज को एक करने की कोशिश करेंगे। 30 अप्रैल को एक बार फिर वह काशी आएंगे। यहां होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे।

नए आपराधिक कानूनों, धाराओं और प्रक्रियाओं की जानकारी जन-जन को कराएं उपलब्ध : मुख्यमंत्री

अचल सम्पत्ति संबंधी अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस के साथ राजस्व का अमला भी सजग और सतर्क रहे

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाए गए नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय प्रणाली को अधिक लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। सभी के लिए अधिक सुलभ, सहायक और कुशल न्याय प्रणाली आवश्यक व्यवस्था, उपकरण और भौतिक संसाधनों की उपलब्धता प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अचल सम्पत्ति संबंधी अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस के साथ राजस्व का अमला भी सजग और सतर्क रहे, साथ ही दोनों

सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बने इन कानूनों और नवीन प्रक्रियाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाना आवश्यक है। न्याय प्रणाली से जुड़ी सभी संस्थाओं में अद्यतन व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए जन-सामान्य को नई धाराओं और प्रक्रियाओं से शीघ्र अतिशीघ्र अवगत कराने के लिए नए आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नवीन आपराधिक कानूनों की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए। मंत्रालय में हुई बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव गृह श्री जे.एन. कंसोटिया, पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पुलिस, जेल, अभियोजन, न्यायिक एवं फॉरेंसिक कर्मियों के बीच अद्यतन तकनीक के उपयोग का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए। सभी हितधारकों में हर स्तर पर बेहतर समन्वय जरूरी है। प्रत्येक स्तर पर विभागों में परस्पर समन्वय भी हो। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों सहित जिन क्षेत्रों में भूमि की दरें तेजी से बढ़ रही है, वहां विशेष सजगता बरती जाए।

बैठक में बताया गया कि समयावधि में चालान के लिए नवीन डैशबोर्ड उपलब्ध है। ई-साक्ष्य की प्रक्रिया भी आरंभ की जा चुकी है। पुलिस थानों तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए न्यायश्रुति सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है और थानों व कंट्रोल रूम में साउंड प्रूफ कक्ष चिन्हित किए जा रहे हैं। ऑनलाइन समन/वारंट मॉड्यूल के अंतर्गत गतिविधियां प्रगति पर हैं। पिछले तीन महीने में 50 प्रतिशत से अधिक वारंट तिथि से पहले इलेक्ट्रानिक रूप से तामील किए गए। इनकी मॉनीटरिंग के लिए सभी जिलों में सेल गठित किए जा चुके हैं। डिजिटल इन्वेस्टिगेशन केलिए टेबलेट्स और लाइव स्कैनर थानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बैठक में डिजिटल धोखाधड़ी, डेटा चोरी जैसे सायबर अपराधों के बारे में जागरूकता के लिए की गई पहल की भी जानकारी दी गई।

घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े

- नई कीमतें आज से लागू होंगी, दिल्ली में अब 853 रुपए का मिलेगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। आज यानी, सोमवार 7 अप्रैल को पेट्रोल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसकी जानकारी दी। अभी दिल्ली में गैस सिलेंडर 803 रुपए में मिलता है। दाम बढ़ने के बाद कीमत 853 रुपए हो जाएगी। वहीं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के गैस सिलेंडर की कीमत 500 से बढ़कर 550 रुपए हो जाएगी।

पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए बढ़ी पर आम लोगों के लिए दाम नहीं बढ़ेंगे- सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है। हालांकि, आधे घंटे बाद ये भी साफ किया कि इससे पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। इसे कच्चे तेल की घटी कीमतों से एडजस्ट किया जाएगा।अभी सरकार पेट्रोल पर 19.90 रुपए लीटर और डीजल पर 15.80 रुपए लीटर एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है। इस बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल पर 21.90 रुपए लीटर और डीजल पर 17.80 रुपए लीटर ड्यूटी लगेगी।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 22°c
न्यूनतम 16°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ मंगलवार, 8 अप्रैल 2025

> जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।
>
> चाणक्य नीति

हिमालय में उड़ने वाला जानवर मिला, देख दुनिया हैरान...

● क्या हरी दीवार बनाने में फेल हैं देश ? ● क्या है जैव विविधता का संकट, जिससे धरती परेशान ● 10 लाख प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा क्यों

नई दिल्ली (एजेंसी)। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में एक उड़ने वाला जानवर मिला है, जिससे देश और दुनिया के वैज्ञानिक हैरान हैं। यह जानवर हिमाचल के लाहौल-स्पीति में मिला है। यह खोज वैज्ञानिकों को बेहद खुशी दे सकता है, क्योंकि इस तरह के पशुओं से भारत की अंतरराष्ट्रीय साख बढ़ती है। वन विभाग के वन्यजीव प्रभाग द्वारा ने जिला की मियार घाटी में इसकी खोज की है। यहां कैमरा टैपिंग सर्वेक्षण के दौरान उड़ने वाली गिलहरी मिली है, जिसे यूपेटॉरस सिनेरेउस (woolly flying squirrel) कहा जाता है। जानते हैं भारत समेत दुनिया के कई देश जैव विविधता के लिए ग्रीन वॉल बनाने में क्यों फेल हो रहे हैं?

सात दशकों तक विलुप्त रही है यह प्रजाति- दरअसल, उत्तर-पश्चिम हिमालय की इस विलक्षण और दुर्लभ प्रजाति को लगभग सात दशकों तक विलुप्त माना जाता था, जब तक कि 1994 में इसकी पुनः खोज नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश में इसकी मौजूदगी देश और दुनिया की जैव विविधता के लिए अहम है। दरअसल, यह सर्वेक्षण हिम तेंदुए की संख्या आकलन के लिए भारत सरकार के एक प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा था, जब यह गिलहरी मिली।

हिम तेंदुआ, लाल लोमड़ी और हिमालयी भेड़िया भी मिला- कैमरा ट्रैप्स ने ऊनी उड़ने वाली गिलहरी के अलावा कई अन्य महत्त्वपूर्ण वन्यजीवों जैसे हिम तेंदुआ, लाल लोमड़ी, हिमालयी भेड़िया और नेवले की मौजूदगी भी देखी गई। ये प्रजातियां आमतौर पर पहाड़ों के ऊपर के क्षेत्रों और चट्टानी ढलानों वाले पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती हैं। यह खोज न केवल मियार घाटी की जैविक विविधता को दर्शाती हैं, बल्कि हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र की समृद्धता और संरक्षण की जरूरत को भी बताती हैं।

क्या होती है जैव विविधता, इनकी दुनिया क्या है- जैव विविधता का मतलब है पृथ्वी पर जीवन की विविधता, जिसमें सभी तरह के पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव और उनके द्वारा बनाए गए पारिस्थितिक तंत्र शामिल हैं। जैव विविधता प्रकृति में हर उस चीज का समर्थन करती है जिसकी हमें जीवित रहने के लिए आवश्यकता होती है, जैसे भोजन, स्वच्छ पानी, दवा और आश्रय। हम जिस जैव विविधता को जानते हैं, उसे मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है-आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता और कामकाज के हिसाब से विविधता।

10 लाख प्रजातियों के विलुप्त होने का मंडरा रहा खतरा- डिफेंडर्सडॉटओआरजी पर छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, यह एक चौंकाने वाली सच्चाई है कि अगर हम जैव विविधता संकट को दूर करने के लिए अभी से कदम नहीं उठाते हैं तो आने वाले दशकों में दुनिया भर में दस लाख प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है। इतनी बड़ी मात्रा में नुकसान का न केवल प्रजातियों पर बल्कि हमारे अपने स्वास्थ्य और कल्याण पर भी अकल्पनीय नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

उत्तरी अमेरिका से कहां चले गए 300 करोड़ पक्षी- 1970 के बाद से उत्तरी अमेरिका से तीन अरब पक्षी गायब हो गए हैं और पिछले 40 वर्षों में अमेरिका में भृंगों की संख्या में 83 प्रतिशत की कमी आई है। अमेरिका के 41 प्रतिशत पारिस्थितिकी तंत्र पहले से ही व्यापक रूप से ढहने के जोखिम में हैं।

बंद पड़ी नल जल योजनाओं को यथा शीघ्र चालू कराएं : कलेक्टर

बैतूल। नल जल योजना के तहत हितग्राहियों को घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए गंभीरता से कार्य करें। बंद पड़ी नल जल योजनाओं को संबंधित ठेकेदार के माध्यम से शीघ्र चालू कराएं। आगामी एक सप्ताह में नल कनेक्शन के निर्धारित लक्ष्य को शत प्रतिशत पूर्ण किया जाएं। यह निर्देश कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने सोमवार को समयसीमा की बैठक में सभी जनपद सीईओ एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को दिए। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने निर्देश दिए कि समस्त विभागीय अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण का रोस्टर बनाकर जिला कार्यालय को शीघ्र भेजें। सभी जिला अधिकारी रोस्टर अनुसार अपने अधीनस्थ कार्यालयों का अनिवार्य रूप से आकस्मिक निरीक्षण भी करें। उन्होंने राजस्व, नगरीय निकायों सहित अन्य विभागों को वसूली के निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के अनुरूप इस माह 15 प्रतिशत वसूली करने के सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा कर सभी जनपद सीईओ, सीएमओ सहित अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया अभियान के निर्धारित समस्त पैरामीटर पर प्रगति लाएं। अभियान के दौरान कोई भी अधिकारी अवकाश पर नहीं जाएगा।

आसाराम को फिर 1 जुलाई तक अंतरिम जमानत

जोधपुर (एजेंसी)। जोधपुर के आश्रम में नाबालिग से रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को गुजरात के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट से भी राहत मिली है। कोर्ट ने उसकी अंतरिम जमानत 1 जुलाई तक बढ़ा दी है।

युवक ने बीच सड़क लड़की को गलत तरीके से छुआ

बेंगलुरु (एजेंसी)। बेंगलुरु के एक वायरल वीडियो में युवक सड़क पर दो लड़कियों के पास जाकर उन्हें गलत तरीके से छूकर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो बेंगलुरु के बीटीएम लेआउट इलाके का है। घटना 3 अप्रैल की है।

सोमवार को जब कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा- इस तरह की घटनाएं बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में होती रहती हैं। हालांकि उन्होंने मामले को लेकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही उन्होंने पुलिस को गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया। छेड़छाड़ के बाद आरोपी भागता दिखा। बेंगलुरु पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है।

सीएम योगी बोले-

2034 में देश में एक साथ चुनाव होंगे !

लखनऊ (एजेंसी)। बार-बार होने वाले चुनाव देश के विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगाते हैं। इससे न केवल समय और संसाधनों की बर्बादी होती है, बल्कि देश की जीडीपी पर भी सीधा असर पड़ता है। 2034 में देश में एक सात चुनाव होने की संभावना है। ये बातें सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कही।

एमपी में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया; याचिका की खारिज

भोपाल (एजेंसी)। मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने में कोई न्यायिक अड़चन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए यह स्पष्ट किया। कोर्ट ने कहा कि 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर कोई रोक नहीं हैं। कमलनाथ सरकार ने 2019 में ओबीसी वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया था। इसके खिलाफ यूथ फॉर इक्वेलिटी संगठन ने विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 8 में न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने इस एसएलपी पर सुनवाई की।

पटना में राहुल गांधी बोले-

आरएसएस-भाजपा जातीय जनगणना नहीं चाहती, लेकिन हम करवा कर रहेंगे

पटना/ बेगूसराय (एजेंसी)। बेगूसराय,पटना (एजेंसी)। सोमवार को बिहार दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने माय एक्सपेरिमेंट्स् विथ ट्रूथ लिखा था। मोदी जी शायद माय एक्सपेरिमेंटस् विथ लाइज लिखेंगे। आरएसएस-भाजपा जातीय जनगणना नहीं चाहती, लेकिन हम करवा कर रहेंगे। शेयर बाजार में भारी गिरावट पर राहुल ने कहा, अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने शेयर बाजार की धज्जियां उड़ी दी है। आज मार्केट धराशाई हो गया है। आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा, देश के संविधान में सावरकर की सोच नहीं है। इसमें महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू और अंबेडकर जैसे लोगों की सोच है। आज इस देश में आदिवासी, दलित सेकंड सिटिजन है।

बेगूसराय में कांग्रेस की पलायन रोको यात्रा में शामिल हुए- राहुल गांधी पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने बेगूसराय में कांग्रेस की पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा में हिस्सा लिया। कन्हैया कुमार के साथ एक किलोमीटर पैदल यात्रा की।

प्रदेश के 13 जिलों में तपिश, लू का अलर्ट

सीजन में पहली बार भोपाल में 40 डिग्री पार, तापमान और बढ़ेगा

भोपाल (नप्र)। राजस्थान से आ रही गर्म हवा के चलते मप्र में भीषण गर्मी ने समय से पहले ही दस्तक दे दी है। भोपाल का तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इस सीजन में यह सबसे ज्यादा है। मौसम वैज्ञानिक वीरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि भोपाल में दिन का अधिकतम तापमान शनिवार की तुलना में 1.5 डिग्री अधिक रहा। अभी तापमान और बढ़ने की संभावना है। सुबह 11 बजे तक पारा 36 डिग्री पहुंच गया था, जबकि दोपहर 2:30 बजे तक यह 39 डिग्री तक चढ़ गया। रतलाम लू की चपेट में आ गया। तापमान 42.6 डिग्री पहुंच गया। प्रदेश के 13 जिलों में तापमान 40 से 42.2 डिग्री के बीच रहा। देशभर में राजस्थान सबसे गर्म ‍राजस्थान के बाड़मेर में रविवार को देश का सर्वाधिक तापमान 45.6 डिग्री दर्ज किया गया।

10 दिन पहले ही इतनी गर्मी

पिछले 5-6 वर्षों की तुलना में इस बार अप्रैल में 10 दिन पहले ही गर्मी महसूस हो रही है। आमतौर पर 40.5 डिग्री का तापमान अप्रैल के मध्य यानी 16-17 तारीख के बाद आता था।

कंगना रनोट बोलीं- पीएम मोदी मनुष्य नहीं अवतार

मंडी (एजेंसी)। हिमाचल के मंडी से भाजपा सांसद एवं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनोट ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी साधारण मानव नहीं अवतार हैं। 2014 तक वह वोट देने भी नहीं जाती थीं। नेताओं से नफरत सी हो गई थी। मगर, अब अच्छा खासा काम छोड़कर

लोग राजनीति में आ गए हैं। क्योंकि अब हमारे पास नरेंद्र मोदी के रूप में अच्छे नेता है। इससे पहले देश को सब खा रहे थे, बर्बाद कर रहे थे।कंगना रनोट ने ये बात सोमवार को मंडी में जोगिंद्रनगर के लडभड़ोल में आयोजित एक जनसभा में कही। इसके दौरान उन्होंने हिमाचल सरकार पर भी जमकर हमला बोला।

पहली बार राजनीतिक मंच पर दिखी शिवराज की बहू अमानत

सीहोर (नप्र)। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बहू अमानत चौहान पहली बार राजनीतिक मंच पर नजर आई। शिवराज के बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान की पत्नी अमानत को सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा क्षेत्र के भैरूंदा में भाजपा के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुईं।

अमानत ने यहां कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनके ससुर शिवराज सिंह इस क्षेत्र के साथ ही प्रदेश और देश की सेवा कर रहे हैं। वह भी बेटी के रूप में क्षेत्र की जनता की सेवा करेगी।

इस कार्यक्रम को अमानत की राजनीति में एंट्री की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। कयास लगाए जा रहे है कि आने वाले समय में वह चौहान परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में क्षेत्र की राजनीतिक जिम्मेदारी संभाल सकती हैं।

कहा- बेटी बनकर सेवा करूंगी- अमानत ने कहा कि भैरूंदा की धरती पर उनका जो स्वागत हुआ है, उससे वह अभिभूत हैं। उन्होंने कार्तिकेय सिंह की पत्नी और क्षेत्र की बेटी के रूप में जनता की सेवा करने का वादा किया। यह कार्यक्रम राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान बुदनी-भैरूंदा क्षेत्र को अपना परिवार मानते हैं और कई बार सार्वजनिक मंचों पर कह चुके हैं कि यहां आने के लिए उनका मन हमेशा आतुर रहता है।

ताइवान पर 6 महीने में चीनी हमला...

ड्रैगन के मंसूबों पर अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, एशिया में छिड़ सकता है भीषण युद्ध

बीजिंग (एजेंसी)। चीन की ओर से ताइवान पर हमले का प्लान बनाया जा रहा है। चीन ने इसके लिए तैयारी कर ली है और इसी साल ये हमला हो सकता है। खुफिया सूत्रों से बातचीत के आधार पर की गई अपनी रिपोर्ट में 19 फोर्टीफाइव ने ये दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अगले छह महीनों में ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। ये ऐसा समय हो रहा है जब चीनी सत्ता के गलियारों में ताइवान पर हमले की मांग बढ़ रही है। बीजिंग में सवाल हो रहा है कि अगर ताइवान को अब नहीं तो कब चीन का हिस्सा बनाया जाएगा।

अमेरिका ने लगातार ताइवान को अपना समर्थन देने के संकेत दिए हैं। हालांकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मानते हैं कि अमेरिका के लिए ताइवान पर चीनी आक्रमण को रोकना मुमकिन नहीं होगा। चीनी सेना और सरकार ताइवान को अपने में मिलाने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। इनमें नाकाबंदी, सैन्य हमले और दूसरे विकल्प शामिल हैं। चीन, ताइवान के साथ जो कर रहा है। उसमें इंटरनेट और संचार के केबलों को काटना, चुनावों में हस्तक्षेप करना और गलत सूचनाएं फैलाना शामिल है। सूत्रों का ये भी मानना है कि अमेरिका इसमें दखल से सकता है और चीन की ये कोशिश ताइवान में बड़ी जंग की वजह बन सकता है।

सैम पित्रोदा बोले-

कांग्रेस में चर्चाएं होती हैं, एग्जीक्यूशन नहीं

● जिम्मेदारों से पूछें- रायपुर-जयपुर सम्मेलन में जो फैसले लिए, वे लागू क्यों नहीं हुए

अहमदाबाद (एजेंसी)। कांग्रेस का 84वां अधिवेशन 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में होने जा रहा है। एक दिन पहले ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा, मुझे गर्व है कि पार्टी गुजरात में अधिवेशन कर रही है। मेरा मानना है कि कांग्रेस के अधिवेशन में आइडियोलॉजी पर अच्छी चर्चा होती है, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। कांग्रेस नेता अपने अंदर गांधीजी के विचार ला पाए तो यह बड़ी उपलब्धि होगी। पित्रोदा ने कहा, इससे पहले रायपुर और जयपुर में सम्मेलन आयोजित किए गए थे। पार्टी को जिम्मेदारों से पूछना चाहिए कि उस समय जो सुझाव आए उनका कितना एग्जीक्यूशन हो पाया। इस बार मैं कांग्रेस नेताओं से हाथ मिलाकर कहूंगा कि आप जो भी निर्णय लें, उसके साथ एक क्रियान्वयन समिति भी बनाएं। उन्हें एक कार्यक्रम दीजिए। संसाधन उपलब्ध कराएं। समय तय करें।

मां बनने वाली है मेरठ जेल में बंद मुस्कान

मेरठ (एजेंसी)। मेरठ में सौरभ हत्याकांड की आरोपी मुस्कान प्रेग्नेंट है। 5 अप्रैल को उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। उसमें प्रेग्नेंसी जैसे लक्षण दिखाई दिए थे। इसके बाद जेल प्रशासन ने मुस्कान का चेकअप करने के लिए डॉक्टर बुलाए। 7 अप्रैल को लेडी डॉक्टर कोमल ने जिला जेल में आकर मुस्कान का टेस्ट किया था। इसमें उसकी प्रेग्नेंसी की पुष्टि हुई।

अगले 11 दिन देश में भीषण गर्मी का अनुमान

बाड़मेर में 26 साल का रिकॉर्ड टूटा, एमपी में हीटवेव

नई दिल्ली (एजेंसी)। 10 अप्रैल तक राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री से ऊपर जा सकता है। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। आज सोमवार को 14 जिलों में हीटवेव का अलर्ट है। बाड़मेर-जैसलमेर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। पिछले 26 साल में बाड़मेर में अप्रैल के पहले हफ्ते में यह सबसे ज्यादा तापमान है। अगले कुछ दिन गर्म से राहत मिलने की संभावना नहीं है।

मध्य प्रदेश में भी भीषण गर्मी ने समय से पहले ही दस्तक दे दी है। रविवार सोमवार को भोपाल का तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इस सीजन में यह सबसे ज्यादा है। प्रदेश के 13 जिलों में तापमान 40 से 42.2 डिग्री के बीच रहा। मौसम विभाग के अनुसार, आज नीमच, मंदसौर, भिंड, मुरैना, श्योपुर और रतलाम में लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 11 दिन तक देश के अधिकतर राज्यों में लू चलने और अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास रहने अनुमान लगाया है। 10 अप्रैल तक राजस्थान, गुजरात के कुछ जिलों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री से ऊपर जा सकता है। उत्तर प्रदेश में इस साल अप्रैल से जून तक तापमान सामान्य से ज्यादा रहने और हीटवेव चलने की आशंका है। दिन का तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहने का अनुमान है। रात का तापमान भी सामान्य से ज्यादा रह सकता है। बीते दिन दिल्ली का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से 3.1 डिग्री ज्यादा है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री कम 18.5 डिग्री सेल्सियस रहा।

भोपाल के निगम ऑफिस में हंगामा, सीवेज गाड़ियां खड़ी कीं

भोपाल (नप्र)। भोपाल के एम्स स्थित नगर निगम जोन-12 ऑफिस के सामने सीवेज शाखा से जुड़े ड्राइवरों ने हंगामा कर दिया। उनका आरोप है कि सीवेज शाखा के दो अधिकारियों ने उन्हें अपशब्द कहे। उन्होंने माता मंदिर स्थित निगम ऑफिस पहुंचकर आपत्ति जताई। वहीं,आज यानी, मंगलवार से वे हड़ताल पर जा सकते हैं।

सोमवार दोपहर में शक्तिनगर स्थित जोन ऑफिस के पास कर्मचारी इकट्ठा हुए और प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सीवेज शाखा से जुड़े कर्मचारी सोनू से महिला एई ने अभद्रता की। सोनू का कहना है कि मेडम ने कुछ और कर्मचारियों को अपशब्द कहे। इसलिए सभी ने विरोध जताया।

सीवेज गाड़ियां नहीं चला रहे- बताया जाता है कि सभी कर्मचारी डोर-टू-डोर सीवेज गाड़ियों का संचालन करते हैं। विवाद के चलते उन्होंने गाड़ियों का संचालन भी बंद कर दिया।

आज नहीं चलाएंगे गाड़ियां- मध्यप्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ अध्यक्ष इरफान अल्ताफ ने बताया कि कल, मंगलवार सुबह सभी ड्राइवर एक जगह इकट्ठा होंगे और कोई गाड़ी नहीं चलाएंगे।

एकांत पार्क में अधिकारी की पत्नी से छेड़छाड़

भोपाल (नप्र)। भोपाल के हबीबगंज थाना क्षेत्र के एकांत पार्क में शनिवार शाम टहलने गई महिला से एक अज्ञात युवक ने छेड़छाड़ की। महिला प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री के कार्यालय में पदस्थ सचिव स्तर के अधिकारी की पत्नी हैं और स्वयं जिला अदालत में कार्यरत हैं। वारदात के समय महिला अकेली थीं, जिससे वह घबरा गईं। अगले दिन उन्होंने अपने पति के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

महिला ने बताया हुलिया, सीसीटीवी फुटेज से पहचान की कोशिश- पुलिस के मुताबिक 48 वर्षीय पीड़िता शनिवार शाम टहलने के लिए एकांत पार्क पहुंची थीं। तभी वहां मौजूद एक युवक ने उनके साथ अभद्रता और अश्लील हरकतें कीं। अचानक हुई इस हरकत से महिला डर गईं और तत्काल पार्क से बाहर निकल गईं। रविवार को उन्होंने अपने पति के साथ हबीबगंज थाने पहुंचकर शिकायत दी। पुलिस ने महिला के बयान के आधार पर युवक का हुलिया तैयार किया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुटी है। पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर जल्द ही आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

चोर बोला-मुझे ढाई लाख की जरूरत, उतने ही ले रहा

खरगोन (नप्र)। खरगोन में रविवार रात को जमींदार मोहल्ले में कोल्ड ड्रिंक सप्लाई करने वाली रॉयल फूड दुकान में चोरी हो गई। काउंटर से ढाई लाख रुपए कैश गायब था।इसी के साथ एक लेटर मिला जिसमें चोर ने व्यापारी से चोरी के लिए माफी मांगी और अगले 6 महीने में पैसे लौटाने का वादा किया।

चोरी की सूचना पर मौके पर पहुंचे एएसआई अशरफ खान ने बताया कि पत्र बरामद कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। पीड़ित व्यापारी जुजर बोहरा के मुताबिक दुकान में रखे बैग में कुल 2 लाख 84 हजार रुपए थे।अज्ञात चोर 2.5 लाख रुपए लेकर गया है। चोर दुकान में प्याऊ के ऊपर की तरफ से घुसा था।

पत्र में लिखा- मुझे पैसों की सख्त जरूरत- अज्ञात चोर ने दुकान में पत्र छोड़ा है। इसमें उसने दुकान मालिक से इसके लिए माफी मांगी। चिट्ठी में उसने लिखा- मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। बहुत कर्जा है मेरे पर। मैं आपके पैसे वापस लौटा दूंगा, पर मुझे थोड़ा समय लगेगा। उसने लिखा-मैंने आपको 3-4 दिन पहले आपकी दुकान पर पैसे गिनते हुए देखा था, तब से आपको देख रहा हूं। पैसे लेने वाले रोज मेरे घर आ रहे हैं, इसलिए न चाहते हुए भी मैं आपकी दुकान से पैसे चुरा रहा हूं।

मैंने पैसे नहीं चुकाए तो मुझे जेल हो जाएगी- अज्ञात चोर आगे लिखता है- अगर मैंने पैसे नहीं चुकाए तो मुझे जेल हो जाएगी, इसलिए में रात में आपकी दुकान की पीछे वाली शटर के ऊपर से आके पैसे ले रहा हूं। मुझे जितना कर्जा चुकाना है, उतने ही पैसे ले रहा हूं। बाकी किसी भी सामान को कुछ नहीं करूंगा।

निष्ठा, धैर्य के साथ न्याय संगत दलील देना लोक अभियोजक का दायित्व : राज्यपाल पटेल

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि निष्ठा और धैर्य के साथ न्यायसंगत दलील देना लोक अभियोजक का दायित्व है। उन्होंने कहा कि तथ्य ही सत्य है। तथ्यों पर आधारित दलील का कानून स्वाभाविक रूप से साथ देता है। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि क्षमताओं और कार्यकुशलता को विकसित कर विभाग को और अधिक ऊँचाइयों पर पहुँचाने की चुनौती में प्रशिक्षण में प्राप्त ज्ञान तथा अनुभवी प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन सहयोगी होगा।

राज्यपाल श्री पटेल सोमवार को केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी (सीएपीटी) भोपाल में आयोजित सहायक लोक अभियोजन अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल श्री पटेल ने इस अवसर पर 10 सहायक लोक अभियोजकों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान किए। उन्होंने अकादमी परिसर में गोल्डन चंपा का पौधा भी लगाया।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का वो स्तम्भ है, जिस पर नागरिकों की गहरी आस्था है। वह उसे सबसे अधिक आदर भाव से देखते हैं। न्याय व्यवस्था में अभियोजन अधिकारियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, बहुआयामी है। उनकी जिम्मेदारी पीड़ितों के लिए मुकदमा चलाने तक सीमित नहीं है। कोर्ट के समक्ष सबूत पेश कर दोषी को सजा और पीड़ित को न्याय दिलाना है। अभियोजन अधिकारी के रूप में अपराध नियंत्रण में पुलिस की जांच में गुणवत्ता लाने, शासकीय विभागों को कानूनी सलाह देने, प्रकरणों में अपील करवाने और पीड़ितों को मुआवजा दिलाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि अभियोजन अधिकारी के रूप में उनके पास वंचित, गरीब और पीड़ित व्यक्ति अत्याचार, अनाचार के खिलाफ न्याय के उसके संघर्ष का रक्षक मानकर आएगा। उस समय उनका संवेदनशील व्यवहार, सहानुभूति और सहयोग न्याय में उसके विश्वास को मजबूत बनाएगा।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि सहायक लोक अभियोजक के रूप में उनका चयन कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद हुआ है, क्योंकि सरकारी नौकरी व्यवसाय मात्र नहीं है। यह वंचितों के जीवन में खुशहाली लाकर देश, प्रदेश और समाज के विकास के द्वारा सुखद भविष्य बनाने की प्रतिबद्ध सेवा का संकल्प है। उन्होंने लोक सेवक के रूप में इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए प्रशिक्षु अधिकारियों का अभिनंदन किया। यह अपेक्षा की है कि न्याय के मंदिर में वह निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य के उच्च मानदण्ड स्थापित करेंगे।

लोकायुक्त न्यायमूर्ति सत्येन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि लोक शांति राज्य का दायित्व है। लोक शांति के लिए अपराधिक न्याय प्रणाली का मजबूत होना आभारभूत आवश्यकता है। इस कार्य में लोक अभियोजकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे न्याय को सुनिश्चित करने के लिए अभियोजन अधिकारी के विहित दायित्वों का निर्वहन जितनी कुशलता और निष्ठा से करेंगे, परिणाम उतने ही अच्छे मिलेंगे।

अपर मुख्य सचिव गृह श्री जे. एन. कंसोटिया ने कहा कि नए विचारों और ऊर्जा के साथ सहायक लोक अभियोजक कार्य को नौकरी की तरह नहीं, सेवा के रुप में करें। उन्होंने न्याय व्यवस्था में लोक अभियोजकों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला और शुभकामनाएं दी।

केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल के निदेशक श्री अनिल किशोर यादव ने अकादमी की स्थापना, प्रशिक्षण व्यवस्था और कार्यक्रमों का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि नवीन कानूनों को लागू होने के 40 घंटों के भीतर अकादमी में उनका प्रशिक्षण प्रारम्भ हो गया था। प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि नये कानून में लोक अभियोजकों की भूमिका काफी मजबूत हो गई है।

संचालक लोक अभियोजन श्री बी. एल. प्रजापति ने स्वागत उद्बोधन में बताया कि सहायक लोक अभियोजन अधिकारियों को 45 दिवस का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। उन्होंने प्रशिक्षण की गतिविधियों का ब्यौरा दिया। बताया कि प्रशिक्षण के दौरान कानूनों के विभिन्न आयामों के साथ योग एवं व्यायाम के सत्र भी आयोजित किए गए है।

समापन सत्र में आभार प्रदर्शन संयुक्त संचालक लोक अभियोजन श्री रामेश्वर कुम्हरे ने आभार प्रदर्शन किया।

प्रदेश में खेलों के उन्नयन के लिये मंत्री सारंग ने ली सभी महापौरों की बैठक

म.प्र. के हर जिले में बनेगा फिट इंडिया क्लब

भोपाल (नप्र)। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने सोमवार को तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में खेलों के उन्नयन के लिये प्रदेश के सभी महापौरों की बैठक ली। बैठक में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहयोग से नगरीय निकायों में खेलों के प्रति सकारात्मक माहौल बनाने, युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने, नगरीय निगम के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के उन्नयन सहित अनेक विषयों पर चर्चा हुई। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि नगरीय निकायों के पास पहले से मौजूद खेल मैदानों व अधोसंरचना का उन्नयन कर खेल गतिविधियों को गति दी जा सकती है। बैठक में नगरीय निकायों और खेल विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष बल दिया गया, जिससे राज्य भर में खेलों का व्यापक प्रसार और विकास सुनिश्चित किया जा सके।

खेल विभाग के सहयोग से नगरीय निकायों में कम्युनिटी स्पोर्ट्स को मिलेगा बढ़ावा- मंत्री श्री सारंग ने कहा कि नगरीय निकायों में कम्युनिटी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहयोग से विभिन्न पहल की जा सकती हैं। इसमें फिट इंडिया क्लब की स्थापना तथा सामुदायिक स्तर पर विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन प्रमुख है। उन्होंने उपस्थित सभी महापौरों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में खेलों के उन्नयन के लिये क्षेत्र चिन्हित कर प्रस्ताव तैयार करें। इससे खेलों के प्रति रुचि को बढ़ावा मिलेगा और स्वस्थ एवं सक्रिय समाज के निर्माण की दिशा में सार्थक कदम उठाए जा सकेंगे।

हर जिले में फिट इंडिया क्लब, हर विधानसभा क्षेत्र में बनेगा आधुनिक खेल परिसर

मंत्री श्री सारंग ने बताया कि भोपाल में प्रदेश का पहला फिट इंडिया क्लब स्थापित किया गया है, जिसका द्वितीय चरण वर्तमान में निर्माणाधीन है। इसी मॉडल को अपनाते हुए प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में सर्वसुविधायुक्त फिट इंडिया क्लब स्थापित किए जाएंगे। इन क्लबों में बच्चों, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी आयु वर्ग के नागरिकों के लिए शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने महापौरों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इन क्लबों की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान कर शीघ्र प्रस्ताव भेजें।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि देश में पहली बार प्रदेश सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में खेल परिसरों के निर्माण की दिशा में कार्य कर रही है। यह पहल युवाओं को खेलों से जोड़ने, प्रतिभाओं को तराशने और खेल के प्रति सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

खेल विभाग के नवाचारों पर हुई चर्चा

बैठक में खेल विभाग द्वारा प्रारंभ किये गये नवाचार- खेलो बढ़ो अभियान, पार्थ, मध्यप्रदेश युवा प्रेरक अभियान पर भी चर्चा हुई। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि नई पीढ़ी को खेलों से जोड़ने के लिये खेलो बढ़ो अभियान की शुरूआत की गई है। इसके साथ ही युवाओं को पुलिस, सेना व पैरा मिलिट्री की शारीरिक व लिखित परीक्षाओं की तैयारी के लिये पार्थ योजना प्रारंभ की गई है। इसके अतिरिक्त, मध्यप्रदेश युवा प्रेरक अभियान के माध्यम से युवाओं में नेतृत्व क्षमता, सामाजिक उत्तरदायित्व और सकारात्मक सोच विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री श्री सारंग ने महापौरों से कहा कि वे अपने नगरीय निकाय क्षेत्रों में इन नवाचारों को सक्रिय रूप से लागू करने में सहयोग करें, जिससे अधिक से अधिक युवा लाभान्वित हो सकें।

नगरीय निकायों में खेल सुविधाओं के विस्तार के लिये महापौरों ने दिये सुझाव

बैठक में उपस्थित महापौरों ने अपने नगरीय निकाय क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विस्तार के लिये सुझाव भी दिये। भोपाल महापौर श्रीमती मालती राय, इंदौर महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव, खंडवा महापौर श्रीमती अमृता यादव, बुरहानपुर महापौर श्रीमती माधुरी पटेल, छिंदवाड़ा महापौर विक्रम सिंह अहके, मुरैना महापौर श्रीमती शारदा राजेंद्र सोलंकी, उज्जैन महापौर श्री मुकेश टेटवाल, रतलाम महापौर श्री प्रहलाद पटेल, देवास महापौर श्री गीता दुर्गेश अग्रवाल, सागर महापौर श्रीमती संगीता तिवारी, रीवा महापौर श्री अजय मिश्रा बाबा, सिंगरौली श्रीमती रानी अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव श्री मनु श्रीवास्तव, खेल संचालक श्री राकेश गुप्ता, संयुक्त संचालक श्री बी.एस. यादव सहित खेल अधिकारी उपस्थित थे।

1 मई से पूरी तरह ऑनलाइन होगा भोपाल कलेक्टोरेट

अधिकारियों को ई-ऑफिस सेटअप तैयार करने के निर्देश, फाइलों का ऑनलाइन अप्रूवल ही मिलेगा

भोपाल (नप्र)। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सोमवार को बैठक लेकर 1 मई को कलेक्टोरेट में ई-ऑफिस सिस्टम लागू करने की बात कही। भोपाल का कलेक्टोरेट 1 मई से ई-ऑफिस हो जाएगा। फाइलों का अप्रूवल ऑनलाइन ही मिलेगा। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सभी विभाग के अधिकारियों को ई-ऑफिस सेटअप तैयार करने को कहा है।

कलेक्टर सिंह ने कहा कि 1 मई से कोई भी फाइल ऑफलाइन नहीं चलेगी। वे भी ऑनलाइन ही अप्रूवल देंगे। वहीं, संबंधित विभाग ई-ऑफिस पोर्टल के जरिए ही फाइलें वरिष्ठ अधिकारियों के पास भेजेंगे। इसके लिए कलेक्टोरेट, जिला पंचायत, नगर निगम आदि ऑफिसों में फाइलों का डेटा बैंक बनाया गया है। एडीएम, एसडीएम और तहसीलदारों की फाइलें भी ऑनलाइन ही चलेगी।सोमवार को कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जिले के अधिकारियों की बैठक ली।

फाइल की हॉर्ड कॉपी मंजूर नहीं होगी- कलेक्टर सिंह ने सोमवार को समयावधि बैठक में अफसरों से कहा कि एक मई से किसी भी फाइल की हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी।

अस्पताल, कोचिंग का फायर ऑडिट होगा- कलेक्टर ने भोपाल के सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोचिंग संस्थान, अस्पताल, होटल, पटाखों की दुकान एवं अन्य संस्थानों का फायर ऑडिट करने को कहा है। वहीं, जिले में समग्र आईडी को आधार से लिंक कराने के कार्य में गति लाने को कहा। एसडीएम को अवैध खनन एवं अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी एडीएम को एसडीएम कोर्ट एवं एसडीएम को तहसीलदार कोर्ट का निरीक्षण करने आदेशित किया गया।

सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में नाराजगी- कलेक्टर सिंह ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए नाराजगी व्यक्त की। कहा कि 50 दिवस से अधिक लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की प्रतिदिन समीक्षा कर शिकायतों का निराकरण करें। उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जनभागीदारी के माध्यम से जिले की नदी, तालाब, जल संरचनाओं का संरक्षण एवं संवर्धन को गंभीरतापूर्वक लेते हुए समस्त संबंधित विभागों की आगामी एक महीने का प्लान तैयार करने के निर्देश दिए।

विद्युत भार (लोड) स्वीकृत करवायें एवं जुर्माने से बचें

भोपाल (नप्र)। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा इन दिनों निम्नदाब के गैर घरेलू और औद्योगिक (पॉवर) उपभोक्ताओं के परिसरों का व्यापक चैकिंग अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के दौरान उपभोक्ता परिसर में विद्युत भार (लोड) में वृद्धि के प्रकरण पकड़े जा रहे हैं। कंपनी द्वारा विद्युत भार की वृद्धि स्वेच्छा से कराने के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक करने का भी अभियान इन दिनों चलाया जा रहा है। कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे कंपनी के पोर्टल पर स्वेच्छिक ऑनलाइन आवेदन कर भार वृद्धि करा लें।

विद्युत भार क्या है

बिजली कंपनी में नवीन कनेक्शन के लिए जब कोई व्यक्ति अधिकृत आवेदन देता है तो उसके परिसर में भार (लोड) की गणना कर भार निर्धारित किया जाता है। इस प्रक्रिया में नया कनेक्शन देने के लिए बिजली कर्मचारी परिसर का लोड सर्वे करते हैं। यह भार (लोड) विद्युत प्रणाली में जोड़ा जाता है। इसलिए इसे संयोजित भार या कनेक्टेड लोड कहा जाता है।

भार की सही गणना

उपभोक्ता को बिजली कंपनी के साथ सहयोग कर भार की सही गणना कराना चाहिए ताकि विद्युत प्रणाली सुचारू रूप से संचालित की जा सके। उपभोक्ता द्वारा परिसर में कनेक्शन लेने के कुछ अन्तराल बाद कुछ नये विद्युत उपकरणों को स्थापित कर भार बढ़ा लिया जाता है। यह बढ़ा भार बिजली कंपनी के कार्यालय में यदि स्वीकृत नहीं कराया जाता है तो चैकिंग के दौरान भार वृद्धि का प्रकरण बन जाता है और उपभोक्ता को जुर्माना भरना पड़ता है।

चैकिंग में पकड़े जाने पर जुर्माना

यदि उपभोक्ता के परिसर में भार वृद्धि का प्रकरण मिलता है तो ऐसे उपभोक्ताओं पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। बढ़े हुए भार की अनुपातिक खपत पर दो गुनी दर से शुल्क वसूली का प्रावधान है। साथ ही विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अंतर्गत भी चैकिंग में अतिरिक्त भार पाए जाने पर ऐसे अतिरिक्त भार को संयोजित करने की दिनांक से बढ़े हुए भार की अनुपातिक खपत पर दोगुनी दर से पेनाल्टी लगाने का प्रावधान है।

सोहेल ने राहुल बन युवती को प्रेम जाल में फांसा

भोपाल के मंदिर में मांग भर शादी हो जाने का भरोसा दिलाया, लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा

भोपाल(नप्र)। भोपाल के कटारा हिल्स इलाके से लोगों ने एक युवक को पकड़ा है। युवक ने अपनी असली पहचान छिपाकर और नाम बदलकर एक युवती से दोस्ती की। फिर उसके साथ गलत काम किया। इतना ही नहीं मंदिर में जाकर मांग भी भर दी और शादी हो जाने का भरोसा दिलाया। आरोपी युवक ने सोशल मीडिया पर युवती से दोस्ती की थी। आरोपी युवक को पुलिस के हवाले किया गया। जहां पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

पुलिस ने बताया कि कटारा हिल्स थाने में एक मुस्लिम युवक पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। मुस्लिम युवक सोहेल खान ने अपना धर्म छुपाकर हिंदू युवती से सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर दोस्ती की। इसके बाद लड़की से मीठी-मीठी बातें करके उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। एक दिन सोहेल खान से बने राहुल ने लड़की से कहा कि चलो दोस्त के घर घुमाकर लाता हूं। मगर, शख्स एक जगह ले गया युवती को और उसके साथ गलत काम किया।

जल्द शादी करने का भरोसा दिलाया था

पीड़िता द्वारा आरोपी की करतूतों का विरोध करने पर आरोपी ने भरोसा दिलाया कि जल्द उससे शादी कर लेगा। जब लड़की ने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी उसे एक मंदिर ले गया। वहां लड़की की मांग भर दी। शंका होने पर लोगों ने मंदिर के बाहर ही आरोपी को पकड़ लिया। उससे पूछताछ करने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ। आरोपी दसवीं फेल है और प्राइवेट नौकरी करता है।

एक महीने पहले संपर्क में आए थे

इस मामले में एडिशनल डीसीपी महावीर सिंह मुजाल्दे का कहना है कि एक महीने पहले दोनों की दोस्ती हुई थी और उस समय उसने अपना नाम राहुल शर्मा बताया था। मंदिर के बाहर पकड़े जाने के बाद खबर फैली तो पता चला कि वह राहुल शर्मा नहीं बल्कि सोहेल खान है। हमने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है।

राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा 1530 अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण : कंषाना

भोपाल (नप्र)। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना ने कहा है कि राज्य सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए लगातार प्रयास रही है। खेती की आधुनिक पद्धतियों, कृषि यंत्रों एवं नवीनतम तकनीकों की जानकारी कृषि विभाग के अधिकारियों को समय-समय पर दी जा रही है, जिससे कि वे क्षेत्र में जाकर किसानों को उनसे अवगत करा सकें। राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वर्ष 2024-25 में 57 प्रशिक्षणों के द्वारा 1530 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

कृषि की आवश्यकता अनुसार विषयों पर प्रशिक्षण

कृषि मंत्री कंषाना ने कहा कि राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान बरखेड़ी कला, भोपाल कृषि की आवश्यकता अनुसार विभिन्न विषयों पर विभागीय अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि विभाग की आत्मा योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 में कृषि एवं संवर्गीय विभाग के अधिकारियों के 54 प्रशिक्षण आयोजित किए गए जिससे 1338 प्रशिक्षणार्थियों को लाभ मिला। आत्मा योजना क्रियान्वयन के लिए 2 रिव्यू वर्कशॉप के माध्यम से 155 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। स्टेट लेवल वर्कशॉप ऑन ट्रेनिंग नीड असेसमेंट के प्रशिक्षण द्वारा 37 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

पिछले एक वर्ष में 30 विषयों पर दिया गया प्रशिक्षण

मंत्री श्री कंषाना ने कहा कि पिछले एक वर्ष में 30 विषयों पर प्रशिक्षण आयोजित किए गए। इनमें सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री फॉर इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम, फार्म मैकेनाइजेशन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सर्टिफिकेशन इश्यूज एंड स्ट्रेटजीज, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर क्वालिटी कंट्रोल एंड लीगल एस्पेक्ट्स, ओरिएंटेशन ऑन फ्लैगशिप स्कीम्स, ऑफिस मैनेजमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड डिपार्टमेंट (एग्जीक्यूटिव), ऑफिस मैनेजमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड डिपार्टमेंट (मिनिस्टीरियल), मार्केट लेड एक्सटेंशन एंड मार्केट लिंकेज, लीडरशिप डेवलपमेंट एंड टीम बिल्डिंग, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल लाइवस्टॉक एंड फोडर प्रोडक्शन, मिलेट्स प्रोडक्शन, रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, आईटी इन एग्रीकल्चर पर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स, जीआई आईपीआर और डब्ल्यूटीओ, रिफ्रेशर ट्रेनिंग कम वर्कशॉप फॉर खरीफ क्रॉप्स, रिफ्रेशर ट्रेनिंग कम वर्कशॉप फॉर रबी क्रॉप्स, सॉइल ट्रेनिंग एंड न्यूट्रीशनल रिकमेंडेशन फॉर एग्रीकल्चर क्रॉप्स, जेंडर सेंसटाइजेशन एंड जेंडर बजटिंग, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनीज, मैनेजमेंट ऑफ मेजर पॉलिफेगस इंसेक्ट्स पेस्टस, आत्मनिर्भर भारत मिशन इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, स्वच्छता एक्शन प्लान, रेनफेड फार्मिंग, प्रेसीजन फार्मिंग एग्रीकल्चर, रिफ्रेशर ट्रेनिंग फॉर आत्मा फंशनरीज और रिफ्रेशर ट्रेनिंग फॉर फॉर्म मैनेजर विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।

संपादकीय

वक्फ बिल : आफ्टर इफेक्ट्स

देश में वक्फ संशोधन विधेयक के कानून बनने के साथ ही उसके सियासी आफ्टर इफेक्ट दिखने लगे हैं। खासकर एनडीए में इस बिल को समर्थन देने वाले दल जद यू, रालोद और रालोपा में मुसलमान पार्टी की नीतियों और नेतृत्व से नाराज होकर लगातार इस्तीफे दे रहे हैं। इसमें भी बिहार में सबसे ज्यादा इस्तीफे उस जद यू से हो रहे हैं, जिसके समर्थन से दिल्ली में मोदी सरकार चल रही है। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं में हालांकि कोई बहुत बड़े नाम नहीं हैं, लेकिन इससे यह संदेश तो जा ही रहा है कि जदयू और रालोद में सब ठीक नहीं है। जो मुसलमान पार्टी छोड़ रहे हैं, उन्हें अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है। हालांकि यह कहना अभी मुश्किल ही है कि इससे जद यू को भारी नुकसान होगा। लेकिन भाजपा ने वक्फ बिल को लेकर साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की जो महीन चाल चली है, उसे बाकी लोग ठीक से बूझ नहीं पा रहे हैं। दरअसल वक्फ बिल पास होने से मुस्लिम संगठनों और नेताओं की वह चाल विफल हो गई, जिसके तहत वो खुद को सेक्युलर कहलाने वाली पार्टियों पर यह दबाव बना रहे थे कि वो वक्फ बिल संसद में ही रूकवा दें। लेकिन वैसा कुछ नहीं रहा। भाजपानीत एनडीए एकजुट रहा। अब तो बिल कानून भी बन गया है। ऐसे में विरोध कर रहे मुस्लिम संगठनों के पास केवल दो ही रास्ते बचे हैं। पहला बिल का कोर्ट में विरोध और दूसरा बिल का सड़कों पर विरोध। जिस तरह से वक्फ विधेयक लाया गया है, उस पर कोर्ट द्वारा तत्काल स्टे दिए जाने की संभावना कम है। यानी मामला कोर्ट में लंबा चलता रहेगा। जहां तक सड़कों पर इसके विरोध का प्रश्न है तो यह भी बहुत दिनों तक खिंचना मुश्किल है। संभव है कि जब मुसलमानों को बिल की असलियत समझ आएगी तो वो खुद ही विरोध करना बंद कर देंगे। लेकिन इससे उन मुस्लिम नेताओं की पोल जरूर खुल जाएगी, जो गरीब मुसलमानों को मनमाने तरीके से भड़का रहे हैं। राजनीति के संदर्भ में देखें तो फिलहाल मुसलमान नेताओंके पार्टी छोड़ने का असर बिहार में ज्यादा दिख सकता है। बिहार में करीब 18 फीसदी मुसलमान है और लगभग 70 सीटें ऐसी हैं, जहां मुस्लिम वोट मायने रखते हैं। ऐसे जद यू को मुस्लिम वोटों से हाथ धोना पड़ सकता है। दूसरी तरफ गैर एनडीए दलों में अब मुस्लिम वोटों को लेकर छीना झपटी मचना तय है। जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि वो विधानसभा चुनाव में 40 फीसदी टिकट मुसलमानों को देंगे। उनके अलावा राजद, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और अन्य पार्टियां भी मुसलमानों को वोट पाने की हर संभव कोशिश करेंगी। लेकिन उनके अति मुस्लिम प्रेम का नतीजा यह भी हो सकता है कि हिंदू वोट नए सिरे से लामबंद हो। इसका असर चुनाव नतीजों पर जरूर दिखेगा। उधर जो मुस्लिम नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, उन पर दबाव है कि वो कौम के हक में भाजपा को समर्थन देने वाले दलों से किनारा करें। लेकिन ये नेता भी आखिर जाएंगे कहां। गैर एनडीए दलों में पहले ही से मुस्लिम नेताओं की कमी नहीं है। ऐसे में जद यू, रालोद या रालोपा छोड़ने वाले मुस्लिम नेताओं का राजनीतिक भविष्य भी अनिश्चित है। कहा तो यह भी जा रहा है कि भाजपा द्वारा छोटे क्षेत्रीय दलों के सफाए का पार्ट टू शुरू हो चुका है। पहली किस्त में महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस निपटी, अब जदयू और रालोद का नंबर है। वैसे भी नीतीश के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठ रहे हैं और जयंत चौधरी के नेतृत्व में उनके पिता जैसी बात नहीं है।

बीमार झीलों को बचाने के लिए नीति और नीयत

नजरिया

पंकज चतुर्वेदी

स्वतंत्र लेखक कई वर्षों तक 'नेशनल बुक ट्रस्ट' से संबद्ध रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर की झीलों का पानी तेजी से गर्म हो रहा है, जिससे ताजे पानी की आपूर्ति और पारिस्थितिक तंत्र को खतरा है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि झीलों के पानी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे सतह और गहरी पानी की परतें प्रभावित हो रही हैं। 'नासा' और 'राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन' के सहयोग से हुए एक अध्ययन के अनुसार, जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में झीलों को तेजी से गर्म कर रहा है। 1980 से 2017 के बीच झीलों की सतह के पानी में 5.5 प्रतिशत और गहरे पानी में 18.6 प्रतिशत तक ऑक्सीजन कम हुई है। 2003 से 2023 के बीच 85 प्रतिशत झीलों में 'हीटवेव' यानि लू के दिन बढ़े हैं।

पानी गर्म होने से ऑक्सीजन घुलने की क्षमता घटती है। 'हीटवेव्स' का बढ़ता दायरा झीलों में करीब 7.7 प्रतिशत ऑक्सीजन की हानि के लिए जिम्मेदार है। यही नहीं,'एल्गल ब्लूम' (शैवाल प्रस्फुटन) की बढ़ती समस्या झीलों के जीवन के लिए नया खतरा है। खेतों के कीटनाशक और पशुओं के मल से पानी में नाइट्रोजन-फॉस्फोरस बढ़ा जिससे शैवाल फैले। ये शैवाल ऑक्सीजन सोखकर 'डेड जोन' बना रहे हैं। 'एल्गल ब्लूम्स' ने ऑक्सीजन की 10 प्रतिशत कमी में योगदान दिया। 55 प्रतिशत ऑक्सीजन की कमी का कारण लगातार बढ़ता तापमान है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो सन् 2100 तक झीलों में 9 प्रतिशत ऑक्सीजन घट सकती है।

कब्जे के लिए सूखती, घरेलू व अन्य निस्तार के कारण बदबू मारती, पानी की आवक के रास्ते में खड़ी रुकावटों से जलहीन होती, सफाई न होने से उथली होती और जलवायु परिवर्तन से जूझती दुनियाभर की झीलें बीमार हो रही हैं। इसका असर समूची प्रकृति के साथ-साथ इंसान पर भी पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका 'अर्थ फ्यूचर' के ताजा अंक में प्रकाशित शोध ने चेतावनी दी है कि जिस तरह मानव-स्वास्थ्य के लिए रणनीति बनाई जाती है, ठीक उसी तरह झीलों की तंदरुस्ती के लिए व्यापक नीति जरूरी है। इसके लिए अनिवार्य है कि झीलों को भी प्राणवान समझा जाए। इस शोध में 10 हेक्टेयर से अधिक फैलाव वाली दुनिया की 14,27,688 झीलों की सेहत का आंकलन किया गया है, जिनमें भारत की 3043 झीलें शामिल हैं।

यह समझना होगा कि झीलें जीवित प्रणालियां हैं, जिन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, प्रसन्न रहने के लिए स्वच्छ पानी, अपने भीतर जीव-जन्तु बनाए रखने के लिए संतुलित ऊर्जा और पोषक तत्वों की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। जैसे-जैसे इंसान झीलों के प्रति निर्मोही हो रहा है, अपने साथ प्रकृति की इन अमूल्य धरोहरों के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रहा है।

इंसान की ही तरह झीलें विभिन्न रोगों की शिकार हो रही हैं, जैसे-तेज बुखार अर्थात अधिक गरम होना, परिसंचरण (जैसे इंसान के शरीर में रक्त-संचरण), श्वसन, पोषण और चयापचय संबंधी मुद्दों से लेकर संक्रमण और विषाक्तता तक झील के स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं।

झीलें बरसात से जितना पानी पाती हैं, उससे दुगना वाष्पित करती हैं। यदि बरसात कम होगी, गर्मी अधिक होने से वाष्पीकरण अधिक होगा और उथलेपन से उनकी भंडारण क्षमता घटेगी तो जाहिर है, झील की सेहत गड़बड़ाएगी। यदि झील की सेहत से बेपरवाही रही तो समूचे पर्यावरणीय तंत्र पर इसका असर होगा, जिसके चलते झील पर निर्भर बड़ी आबादी के सामाजिक-आर्थिक जीवन में भूचाल या जाएगा।

भारत का हर तालाब अपने आसपास भू-वैज्ञानिक इतिहास और पर्यावरणीय महत्व की एक अनूठी कहानी समेटे हुए है। स्वस्थ झील-तालाब 'वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों' को पाने की राह में अतुलनीय पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। यदि तालाब को बीमार होने से बचाने या फिर बीमार झील के उपचार की बेहतर रणनीति न बनाई जाए तो उसके आसपास रहने वाले लोग और वन्य जगत भी अस्वस्थ हो जाता है।

एक झील के पानी का निर्मल और पर्याप्त होना कई तरह से समूचे परिवेश के बेहतर स्वास्थ्य का परिचायक होता है। यह जलचरों, जैसे- कछुआ, मछली के पनपने और उनके आवागमन को प्रभावित करता ही है, पानी कम होने पर स्थानीय सामाजिक और राजनीतिक विग्रह भी उपजाता है। भारत जैसे देश में जहां, तालाबों के किनारे कई पर्व, मान्यताएं और धार्मिक गतिविधियां अनिवार्य मानी जाती हैं, उनका अस्तित्व ही झील की सेहत पर निर्भर है। झील-तालाब के बीमार होने से इलाके का कार्बन और ताप-अवशोषण प्रभावित होता है, जो जैव-विविधता की क्षति और बाढ़-सूखे के रूप में सामने आता है। स्थानीय समाज का जलस्रोत यदि सेहतमंद न हो तो जलजनित रोग बढ़ते हैं।

आखिर कोई झील बीमार कैसे होती है? यदि उसमें पानी की मात्रा कम है तो थोड़ी गर्मी में ही उसका तापमान बढ़ेगा, अधिक गर्मी हुई तो तेजी से वाष्पीकरण होकर जल- भंडार खाली होगा। तालाब- झील में ऑक्सीजन की मात्रा कम होना भी खतरनाक है। यह अन्य जलचरों और वनस्पति के लिए जानलेवा होता है। जलकुंभी या फिर पानी में अधिक मात्रा में दूषित अपशिष्ठ का मिलना, गंदे पानी का निस्तार ऑक्सीजन कम होने के मूल कारक हैं। इससे पानी की क्षारीयता भी बढ़ती है जो किसी तालाब के गंभीर बीमार होने का लक्षण है। गौर करें ठीक इंसान के स्वस्थ्य-शरीर की ही तरह झीलों को भी पर्याप्त ऑक्सीजन और अति-क्षारीयता या अम्लीयता से मुक्ति चाहिए होती है। एक बात और - यदि दरिया का पानी दुरुस्त न हो तो उससे उगने वाले उत्पाद भी पौष्टिक नहीं रहेंगे।

जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान में वृद्धि झीलों की सेहत को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। भारी जल-दोहन और बरसात की अनियमितता के कारण कई झीलों में जलस्तर तेजी से नीचे गिरा है, जबकि दूसरी तरफ पेयजल, सिंचाई और मछली पालन आदि में पानी की खपत बढ़ी है। इससे झीलों का पोषण गड़बड़ा जाता है, उसमें पोषक तत्वों की सांद्रता या तो अधिक हो जाती है या फिर बहुत कम हो जाती है। इस तरह झील का पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है। पोषक तत्वों की अचानक अधिकता होने से जलाशयों की ऊपरी सतह पर हरे रंग की परत जमती है। इसे वैज्ञानिक भाषा में 'यूट्रोफिकेशन' कहते हैं।

झीलों के जल का अधिक गरम होना और आयनीकरण के साथ अम्लीकरण, लवणीकरण और शैवाल के कारण बदरंग होना, ये सभी झील के चयापचय संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। खनन गतिविधियों, औद्योगिक प्रदूषण, वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन युक्त रसायनों के बढ़ने से पानी की 'पीएच कीमत' छह से कम हो जाती है। यदि पानी में पहले से नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड हों तो यह और कम हो सकती है। यह तालाब-झील की पानी की गुणवत्ता के लिए घातक है और इससे कई संवेदनशील सूक्ष्मजीवों, पौधों और जानवरों के विकास और प्रजनन पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। कई बार मछलियाँ इसके चलते मर जाती हैं।

आज आवश्यकता है कि देश के हर जलाशय की साल में दो बार जल गुणवत्ता की जांच हो और यदि किसी तरह का असंतुलन हो तो त्वरित उपचार किया जाए। किसी भी तालाब के आसपास पारंपरिक पेड़ों की प्रजातियों, उन पर बसने वाले पक्षियों के पर्यावास और झीलों-तालाबों में मछली या अन्य उत्पाद उगाने के लिए किसी भी तरह के रासायनिक कीटनाशक या पोषक के इस्तेमाल पर रोक लगे। झीलों में जमा गाद की नियमित सफाई के अलावा, उसमें कीटनाशकों के इस्तेमाल, बाहरी प्रजाति की मछलियों के बीज डालने, नालियों को जोड़ने पर पाबंदी के साथ-साथ किसी भी झील के नैसर्गिक जल-आवक मार्ग को अविरल बनाए रखना अनिवार्य है। (सप्रेस)

जंगल और जीवन का टकराव का समाधान

पर्यावरण

नृपेन्द्र अभिषेक नृप

लेखक स्तंभकार हैं।

भारत के दक्षिण-पश्चिमी कोने में स्थित केरल अपनी जैव विविधता, सघन वनों और समृद्ध पारिस्थितिकी के लिए जाना जाता है। यहाँ की लगभग 29 प्रतिशत भूमि वनाच्छादित है, जो हाथियों, बाघों, तेंदुओं, भालुओं और विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में जंगलों के आसपास के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वन्यजीवों का बढ़ता हस्तक्षेप मानव-वन्यजीव संघर्ष की गंभीर समस्या को जन्म दे रहा है। यह संघर्ष केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं रह गया है, बल्कि इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम भी सामने आ रहे हैं।

वन्यजीवों और मनुष्यों के बीच टकराव के कई कारण हैं, जिनमें जंगलों का विखंडन, बढ़ती मानव आबादी, कृषि विस्तार, पर्यटन, और जलवायु परिवर्तन प्रमुख हैं। केरल के कुछ इलाकों में हाथियों, तेंदुओं और जंगली सूअरों द्वारा फसलों को नुकसान पहुँचाने की घटनाएँ आम हो गई हैं। इसके अलावा, जंगली जानवरों के हमलों से मानव हताहतों की संख्या भी चिंता का विषय बनी हुई है। हालांकि वन विभाग के आँकड़े बताते हैं कि जंगली हाथियों की संख्या में 7 प्रतिशत की गिरावट आई है और वन्यजीवों से जुड़ी मौतों में भी कमी आई है, लेकिन समस्या की जड़ें कहीं अधिक गहरी हैं।

मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रमुख कारण

केरल के कई जंगलों में बड़े पैमाने पर वन्यजीवों का विचरण होता है, लेकिन जैसे-जैसे जंगलों के किनारे बसे गाँवों और कस्बों का विस्तार हुआ है, वैसे-वैसे यह संघर्ष तीव्र होता गया है। आवास विखंडन, विशेष रूप से अरलम फार्म (कन्नूर) और चिन्नाक्कनाल (इडुक्की) जैसे हाथी गलियारों में, जंगली हाथियों और अन्य वन्यजीवों को मानव बस्तियों की ओर धकेल रहा है। जंगलों में मिलने वाले प्राकृतिक भोजन की कमी और औद्योगिक मोनोकल्चर प्लांटेशन (जैसे-यूकेलिप्टस और रबर के बागान) ने जानवरों को भोजन की तलाश में बस्तियों में घुसने के लिए मजबूर कर दिया है।

इसके अलावा, जंगलों के पास पर्यटन के बढ़ते प्रभाव ने भी वन्यजीवों के व्यवहार को प्रभावित किया है। पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक और खाद्य अपशिष्टों के निपटान में लापरवाही के कारण जानवर भोजन के लिए बस्तियों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। जंगलों के आसपास के क्षेत्रों में पालतू मवेशियों के चरने की प्रवृत्ति भी वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासों को प्रभावित कर रही है।

वन्यजीवों से प्रभावित समुदाय और उनकी समस्याएँ

सबसे अधिक प्रभावित वर्ग वे ग्रामीण और आदिवासी समुदाय हैं, जो परंपरागत रूप से जंगलों में रहते आए हैं और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। केरल के 36 जनजातीय समुदायों के पास वन्यजीवों से निपटने के लिए पारंपरिक ज्ञान और तकनीकें हैं, लेकिन उन्हें नीति-निर्माण में शामिल नहीं किया जाता। पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि जंगली हाथियों और अन्य वन्यजीवों के हमलों में मरने वाले लोगों में से अधिकांश आदिवासी समुदायों से होते हैं। यह विडंबना ही है कि जो समुदाय सदियों से जंगलों के साथ सामंजस्य में रहते आए हैं, वे ही आज इस संघर्ष के सबसे बड़े शिकार बन रहे हैं।

सरकार द्वारा घोषित यह प्रयास कि आदिवासी समुदायों के पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण और मूल्यांकन किया जाएगा, एक स्वागतयोग्य कदम है। यदि इन समुदायों की पारंपरिक तकनीकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा जाए और उन्हें नीति-निर्माण में सम्मिलित किया जाए, तो यह मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन में एक नया मार्ग खोल सकता है।

सरकार की नीतियाँ और उनके प्रभाव

केरल सरकार ने वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 2022 में, सरकार ने स्थानीय निकायों को खेतों को नुकसान पहुँचाने वाले जंगली सूअरों को खत्म करने की अनुमति दी। इसके अलावा, 2023 में मानव-वन्यजीव संघर्ष को 'राज्य-विशिष्ट आपदा' के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिससे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार मिला। हालाँकि, पर्यावरणविदों और वन्यजीव संरक्षण समूहों का मानना है कि वन्यजीवों को मारने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा, बल्कि दीर्घकालिक उपायों की जरूरत है।

कुछ वर्गों द्वारा यह तर्क दिया जा रहा है कि केरल में वन्यजीवों की संख्या बढ़ रही है, और इसीलिए संघर्ष भी बढ़ रहा है। लेकिन वन विभाग के आँकड़े इस तर्क का खंडन करते हैं। जंगली हाथियों की संख्या में गिरावट आई है, और पिछले कुछ वर्षों में वन्यजीवों के कारण होने वाली मौतों की संख्या में भी कमी देखी गई है। फिर भी, यह आत्मसंतोष का कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगलों का विखंडन और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएँ लगातार बढ़ रही हैं।

संभावित समाधान

मानव-वन्यजीव संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए केवल तात्कालिक उपायों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाते हुए पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं को संतुलित करना आवश्यक है। सरकार को चाहिए कि वह वन क्षेत्रों को पुनर्स्थापित करने और जैव विविधता बनाए रखने के प्रयासों को तेज करे। वन विभाग द्वारा अब तक 5,031 हेक्टेयर प्राकृतिक वन को बहाल किया गया है, और जंगलों में तालाब तथा चेक डैम बनाए गए हैं, जो सकारात्मक संकेत हैं। लेकिन यह प्रयास व्यापक स्तर पर और प्रभावी तरीके से किए जाने की जरूरत है।

सहभागी वन और वन्यजीव प्रबंधन की अवधारणा को अपनाते हुए स्थानीय समुदायों को नीति-निर्माण में शामिल करना चाहिए। यदि आदिवासी समुदायों के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर व्यावहारिक समाधान विकसित किए जाएँ, तो मानव-वन्यजीव संघर्ष को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

इसके अलावा, पर्यटन स्थलों पर कचरा प्रबंधन को सख्ती से लागू करने की जरूरत है ताकि वन्यजीव भोजन की तलाश में बस्तियों की ओर आकर्षित न हों। औद्योगिक मोनोकल्चर प्लांटेशन की जगह मिश्रित वनस्पतियों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि वन्यजीवों को पर्याप्त प्राकृतिक भोजन मिल सके।

केरल में मानव-वन्यजीव संघर्ष एक जटिल समस्या है, जिसका समाधान केवल कानूनों और नीतियों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए एक संतुलित और समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। वन्यजीवों के संरक्षण और मानवीय सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जरूरत है। जंगलों और मानव बस्तियों के बीच संघर्ष को कम करने के लिए प्राकृतिक आवासों की रक्षा, स्थानीय समुदायों की भागीदारी, और वन्यजीव प्रबंधन में नवाचार को बढ़ावा देना ही इस समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। यदि सरकार, स्थानीय निकाय, वन विभाग और समुदाय मिलकर कार्य करें, तो यह संभव है कि केरल में मानव-वन्यजीव संघर्ष को एक नियंत्रित और संतुलित रूप दिया जा सके।

रेसिप्रोकल टैरिफ

निर्मल हास्य

रमेश रंजन त्रिपाठी

लेखक व्यंग्यकार हैं।

श्रीमती जी द्वारा घरेलू रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद उसकी अकड़ के शेयर धड़ाम से गिर गए। चेहरे पर तनाव के बाढ़ का पानी लाल निशान तक पहुँचने की कोशिश करने लगा। हुआ यह था कि सुबह आँख खुलने पर चाय देते हुए पत्नी ने तत्काल प्रभाव से नियम लागू कर दिया कि वह घर में उतने ही काम करेंगी जितना वह करेगा। इसी के साथ यह आदेश भी सुना दिया कि सुबह की चाय उन्होंने बनाई है इसलिए नाश्ता उसे तैयार करना होगा। श्रीमती जी ने कुशल कूटनीतिज्ञ की भांति बता दिया कि वे दोनों जॉब पर जाते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं, दिनभर वर्कप्लेस में खटते हैं और थकेहारे लौटते हैं, इसलिए घर के कामकाज में भी बराबरी से एक-दूसरे की मदद करनी होगी। हाथ में पकड़ी हुई चाय को लेकर वह सोच में पड़ गया कि वह 'बेड टी' थी या 'बैड टी'?

बिना किसी पूर्व सूचना के और सोचने-समझने या अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना जारी किए गए इस अध्यादेश की अपील के लिए कोई कोर्ट नहीं थी। दया याचिका भी घरवाली के सामने पेश करनी पड़ती। तभी रेडियो पर गूँजती तलत महमूद की मखमली आवाज, 'मोहब्बत ही न जो समझे वो जालिम प्यार क्या जाने' में उसे डिप्रेशन की स्पेलिंग के साज बजते सुनाई देने लगे। किचन में घुसते हुए उसने सुना- 'हम दोनों डिनर बारी-बारी से बनाएँगे। जैसा स्वाद तुम्हारे खाने का होगा, मैं भी वही ज़ायका परोसूँगी।'

'यह तो नाइंसाफी है', समझना मुश्किल था कि वह गिड़गिड़ा रहा था या उलाहना दे रहा था- 'तुम जानती हो, मुझे खाना बनाना नहीं आता।'

'सीख जाओगे,' उसकी लूज बॉल पर चौका तो पड़ना ही था- 'किस्मत अच्छी है तुम्हारी कि लंच के लिए ऑफिस में कैंटीन है। और, स्वाद बदलने के लिए घर में ऑनलाइन खाना मँगवाने की छूट है।'

अपने हाथ का बना नाश्ता करने के बाद व्रत-उपवास जैसे शब्दों पर उसका प्रेम रह-रहकर उमड़ने लगा। वह डर गया कि सचमुच फास्ट रखने के चक्कर में न पड़ जाए। उससे बड़ी घबराहट यह थी कि श्रीमती जी के रेसिप्रोकल कामकाज के टैरिफ की मार ने अगर ऑनलाइन ऑर्डर को बढ़ावा दिया तो स्टॉक एक्सचेंज के बटुआ 'बुल' को 'बेयर' बनने में देर नहीं लगेगी।

वह समझ गया कि 'रेसिप्रोकल' का मुखौटा लगाकर आई इस मुसीबत से निपटने के लिए खुद ही कुछ करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास न तो चारेक साल जैसी कोई समयसीमा की तसल्ली थी और न ही दूसरों के साथ नया गुट बनाने की छूट! उसने अपने संसाधनों पर ध्यान केंद्रित किया और 'हिम्मत-ए-मर्दां मदद-ए-खुदा' पर यकीन करते हुए शेविंग करना बंद कर दिया। हफ्ते भर में श्रीमती जी के मायके में शादी समारोह में शामिल होने का अवसर आ गया। जिस दिन निकलना था, पत्नी ने टोक दिया- 'ऐसे देवदास बनकर शादी में चलोगे क्या? ये बेतरतीबी से दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है?'

'आजकल फैशन है दाढ़ी रखने का'। उसने अन्यमनस्कता दिखाते हुए जवाब दे दिया। 'फैशनेबल दाढ़ी ऐसी नहीं होती', श्रीमती जी ने मुँह बिचकाया- 'उस दाढ़ी की सेवा आसान नहीं होती। चलो, जल्दी से क्लीन शेव हो जाओ।'

'तुमने पूरा ध्यान नहीं दिया', वह मुस्कुराया- 'मैंने बाल कटाने भी बंद कर दिए हैं। व्यस्तता इतनी बढ़ गई है कि ऐसे अनप्रॉडक्टिव कामों के लिए समय नहीं मिलता और पारस्परिक शर्तों के लिहाज से भी यह मामला एकतरफा है।'

श्रीमती जी की हँसी निकल गई। फिर कुछ सोचती हुई बोलीं- 'मेरी तरह क्लीन शेव हो जाओ वरना मुझे दाढ़ी-मूँछ बढ़ाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे।' वह इस पैंतरे की वजह से चित होनेवाला ही था कि दिमाग की बत्ती जल गई- 'मुझे तुम्हारी दाढ़ी-मूँछ से कोई दिक्कत नहीं होगी।'

श्रीमती जी की प्रतिक्रिया देखने लायक थी। यह तो समझ ही गए होंगे कि 'घरेलू रेसिप्रोकल टैरिफ' का आदेश तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया था। उसने दरियादिली दिखाते हुए कुछ आइटम पर पारस्परिक पाबंदी को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

आपके शांत रहने में छुपी है आपके घर की शांति

व्यंग्य

भूपेन्द्र भारतीय

लेखक व्यंग्यकार हैं।

आजकल हर तरफ विवादित बयानों का हल्ला है। देश की सबसे बड़ी पंचायत से लेकर गली मोहल्लों में हर कोई विवादित बयान के तीर छोड़ रहे हैं। अब तो अकलमंद जैसी बातें भी करो तो लगता है यह बात विवादित तो नहीं हो जाएगी। दूसरे के हित की बात करना भी विवादित माना जाने लगा। वर्तमान स्थिति पर कोई बात करो कि विवाद खड़ा हो जाता है। अभी दो दिन पहले की ही बात है 'मैं गलती से दिन में अपने घर पर था। अतिथि कक्ष में मेरे सामने ही झाड़ू पड़ा था, मैंने बस इतना कह दिया कि यह झाड़ू यहां किसने पटक दिया ! फिर क्या था, मेरी इस छोटीसी बात को विवादित बयान मान लिया गया।' मेरा घर कुछ ही देर में जैसे संसद सदन की भारी हंगामेदार बहस की भेंट चढ़ गया हो। उस दिन घर की अधिकांश कार्यवाही बंद रही। सब अपने अपने कक्षों में अपने अपने मोबाइल के साथ देश दुनिया की कार्यवाही देखते रहे। किसी ने किसी के साथ कोई बातचीत नहीं की। बयान ही ऐसा दिया था। विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष को अपनी राजनीति करने का अवसर मिल गया।

इसलिए आजकल मैं किसी भी तरह के बयान देने से बचता हूँ। अपनी गली की आरसीसी सड़क उखड़ गई हो या फिर मेरे घर के पीछे वाली नाली कब से ही साफ नहीं हुई। ऐसे किसी विवादित विषय पर मैं बयान देने से बचता हूँ। वैसे दिनभर में कोई न कोई ऐसी बात पूछ ही लेता है जिसका जवाब विवादित बयान का रूप ले सकता है। इसलिए मैं अब छोटीमोटी बातों का जवाब देने से बचता हूँ।

हाँ बड़े विषय पर जवाब देने में इतनी परेशानी नहीं होती है। जैसे वर्तमान समय में अमेरिका में लोकतंत्र की क्या स्थिति है ? रूस-यूक्रेन का युद्ध कब समाप्त होगा ? चीन की वर्तमान विदेश नीति क्या है ? 2047 में भारत विकसित राष्ट्र कैसे बन सकता है। ऐसे जवाब देना मेरे बाएं हाथ का काम हो गया है। लेकिन मुझसे कोई पूछ ले आपके घर में लोकतंत्र की क्या स्थिति है, तो मेरे लिए इसका जवाब देना कठिन हो गया है। फिर प्रतिदिन शाम को घर भी तो जाना होता है। भला घर में रहना भी तो है ! आजकल नया घर बनाना कितना मंहगा हो गया है और विदेश जा नहीं सकते। विदेश वाले उधर से उठाकर इधर छोड़ रहे हैं। अच्छा है घरेलू मामले में बयान ही ना दो।

वैसे बयान देने का अपना मजा है लेकिन इनसे उत्पन्न होने वाले विवादों का ओर बड़ा झंझट रहता है। कई बार इससे घर व बाहर की सरकारें तक संकट में आ जाती है। सरकार को बैकफुट पर आना पड़ता है। सरकार गिर भी सकती है। पीछले रविवार की ही बात है, मेरे छोटे से बयान देने पर मुझे दिनभर बैकफुट पर रहना पड़ा। 'मैंने रविवारीय अखबार पढ़ते हुए बस इतना सा बोल दिया था कि देखो, महिलाएं कितना आगे बढ़ गई है ! अपनी सुनीता जी नौ माह अंतरिक्ष में रहकर सफलता पूर्वक वापस पृथ्वी पर आ गई और तुमसे दरवाजे पर खड़े सब्जी वाले से सब्जी नहीं ली जाती !' फिर क्या था ! अपने इस बयान पर दिनभर लीपापोती करता रहा। क्षमा की मुद्रा में आना पड़ा। घर का पृथ्वी-आकाश-अंतरिक्ष एक हो गया। कितनी ही सुनीतायें श्रीमती के शरीर में आने लगी। शाम को पानी-पुरी खिलाकर विवादित बयान की खानापूर्ति की। उस दिन के बाद से अखबार की कैसी ही अच्छी बुरी खबर हो मन ही मन पड़ता हूँ। मेरे शांति निवास में शांति बनी रहती है।

वैसे विवादित बयानों से मैं ही दूरी नहीं बनाता हूँ। बहुमत वाली सरकार भी प्रयास करती है कि ऐसे बयानों से दूरी बनाकर रखी जाना चाहिए। राजनीतिक दल तो बकायदा इसके लिए गाईडलाईन जारी करते है। विवादित बयानों से बचने के लिए दल में नये कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण रखा जाता है। लेकिन आधुनिक सूचना क्रांति युग में इसका पालन करना बहुत कठिन होता जा रहा है। पहले के समय में दादी-नानी नवदंपति के कानों में फूंक देती थी कि बेटा-बेटी दोनों आपस में शुरुआत में कम ही बोलना। तुम्हारे जीवन में विवाद नहीं होगा। अब आजकल दादी-नानी की कोई सुनता नहीं। दादी-नानी भी गाँव में रह गई। नवदंपति विवाह करते ही शहरों की ओर भागते हैं। नवदंपति विवाह गांठ बंधने से पहले ही मोबाइल पर इतनी बात कर लेते हैं कि विवाह बाद सिर्फ विवाद करना ही बाकी बचा रहता है। ऐसे में कोई बयानबाजी से दूर रहे भी तो कितना दूर रहे !

खैर मैंने तो विवादित बयानों से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। आप भी कर ही दो। आपके घर की शांति आपके शांत रहने में छुपी है। जो मिले उसे ग्रहण करो। क्या रखा है हर बात का जवाब देने में। हर घटना पर सोशल मीडिया में पोस्ट करना भी विवाद को जन्म देना है। भले फिर कोई इतिहास में से गड़े मुर्दे निकाले या फिर कोई कमअक्ल हमारे किसी नायक पर ऊलजलूल बयानबाजी करें। देश व समाज की प्रगति रूकने वाली नहीं है, आपके-मेरे बयानबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ स्वयं की शांति जा सकती है। इसलिए समय जिस तरह से चुपचाप निरंतर आगे बढ़ रहा है, हम भी शांति का मार्ग पकड़ते हुए आगे बढ़ते रहे... !

स्थापना दिवस विशेष : प्रगतिशील लेखक

सुसंस्कृति परिहार

अभिव्यक्ति के खतरे उठाने के लिए प्रतिबद्ध हों

प्रेमचंद को रूढ़िवादी लेखकों ने घृणा का प्रचारक एवं ब्राह्मण निंदक घोषित कर दिया मगर हंस,प्रभा एवं रूपाभ जैसी पत्रिकाओं ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। प्रेमचंद के साथ, फ़िराक़,निराला ,पंत, महादेवी, बालकृष्ण शर्मा नवीन जैसे हिंदी-उर्दू के प्रतिष्ठित लेखक हो गये। बाद में रांगेय राघव, रामधारी सिंह दिनकर, राहुल सांकृत्यायन , शिवदानसिंह चौहान, नरेंद्र शर्मा, रामकृष्ण बैनीपुरी , नरोत्तम नागर, प्रकाशचंद गुप्ता ,भगवतशरण उपाध्याय एवं रामविलास शर्मा जैसे कवि,लेखक, कथाकार,समीक्षक बड़ी संख्या में प्रगतिशील लेखक संघ के बैनर तले आ गये। वहीं कविवर रवीन्द्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्र देव, सरोजनी नायडू आदि प्रसिद्ध नेताओं ने प्रगतिशील लेखक संघ का दिल से स्वागत किया।

9 अप्रैल सन् 1936 प्रगतिशील लेखक संघ का स्थापना दिवस है। इसे प्रगतिशील साहित्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सन् 1936 में लखनऊ में 9-10 अप्रैल को प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की। इसका अंकुरण लंदन में 7-8 भारतीय छात्रों की टोली ने किया था। इस टोली में मुल्क राज आनंद और सज़्ज़ाद ज़हीर प्रमुख थे। इसका मूल उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्राज्यवाद और फ़ासिज़्म से संस्कृति की रक्षा के लिए विश्व भर के संस्कृति कर्मियों को लामबंद करना था। इससे पूर्व सन 1934 में रूस में सोवियत संघ तथा 1935 में पेरिस में विश्व लेखक अधिवेशन हुआ जिसने इन छात्रों को प्रेरणा दी। भारत में इस संगठन के जन्मते ही इसे विदेशी संगठन कहकर प्रतिक्रियावादियों ने विरोध शुरू कर दिया, लेकिन सामाजिक- आर्थिक दृष्टि से साहित्य के क्षेत्र में जो नई सोच उत्पन्न हुई उसमें मज़दूर, किसान के अलावा आम शोषित, दलित, पीड़ित सब शामिल हो गए जिससे स्वाधीनता आन्दोलन को बल मिला।

वहीं दूसरी ओर प्रेमचंद को रूढ़िवादी लेखकों ने घृणा का प्रचारक एवं ब्राह्मण निंदक घोषित कर दिया मगर हंस,प्रभा एवं रूपाभ जैसी पत्रिकाओं ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। प्रेमचंद के साथ, फ़िराक़,निराला ,पंत, महादेवी, बालकृष्ण शर्मा नवीन जैसे हिंदी-उर्दू के प्रतिष्ठित लेखक हो गये। बाद में रांगेय राघव, रामधारी सिंह दिनकर, राहुल सांकृत्यायन , शिवदानसिंह चौहान, नरेंद्र शर्मा, रामकृष्ण बैनीपुरी , नरोत्तम नागर ,प्रकाशचंद गुप्ता,भगवतशरण उपाध्याय एवं रामविलास शर्मा जैसे कवि, लेखक, कथाकार,समीक्षक बड़ी संख्या में प्रगतिशील लेखक संघ के बैनर तले आ गये। वहीं कविवर रवीन्द्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्र देव, सरोजनी नायडू आदि प्रसिद्ध नेताओं ने प्रगतिशील लेखक संघ का दिल से स्वागत किया।

प्रगतिशील लेखक संघ के बनने के बाद साहित्य का स्वरूप बदला। उर्दू शायरी भी इससे अछूती नहीं रही। वह आशिक- माशूका के दायरे से निकलकर आम जनता की दिक्कतों,उसकी लड़ाई,दुखदर्द को अपने में समेटने लगी तथा पीड़ित, शोषित वर्ग को सजग बनाकर हौसला अफ़ज़ाई करने लगी । कविता के क्षेत्र में भी जबरदस्त परिवर्तन आया। छंदबद्धता की बाधा को निराला ने तोड़ना शुरू किया। भावों की जगह विचारों ने ली।जीवन की सच्चाईयां एवं विरोध के स्वर लेखन में उभरे। अलंकरणों का स्थान बिम्बों ने लिया।

प्रगतिशील लेखक संघ के गतिशील होने के बाद जीवन की सच्चाइयां और अनुभूतियां यथार्थ रूप में मुखर होने लगीं। यह बदलाव संपूर्ण देश की भाषाओं में लिखे साहित्य में भी साथ-साथ आया। साहित्य अब विरोध की सार्थक अभिव्यक्ति बन एक आंदोलन के रूप में आ गया था जिसमें शोषणमुक्त भारत ही मूलतः प्रगतिशील लेखन का स्वप्न था।

लेकिन आज़ादी के बाद भी जब परिदृश्य नहीं बदला सरकार आम जन की पीड़ा के साथ नज़र नहीं आई, तो सरकार से इन लेखकों का मोहभंग हुआ और तत्कालीन लेखकों ने शासन की रीति-नीति के विरुद्ध लिखना प्रारंभ किया जो उनका दायित्व था। नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ, हरिशंकर परसाई से प्रारंभ हुआ यह लेखन एक बार फिर समूचे देश में शुरू किया गया जो वर्तमान में अभी तक जारी है। लेकिन दक्षिण पंथी विचारों वाली सरकार के चलते आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ख़तरे में है। सरकार विरोधी लेखन निशाने पर है ।हमारे पांच प्रगतिशील विचारक डॉ. नरेद्र दाभोलकर, कामरेड गोविंद पानसरे,डॉ.एम.एम.कलबुर्गी और संपादक गौरी लंकेश की जिस तरह हत्या की गई वह ना केवल चिंतनीय है बल्कि प्रगतिशील सोच पर विराम लगाने की साज़िश लगती है।

हालांकि इस समय संसार की प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी शक्तियों में अनवरत यह संग्राम चल रहा है। पूंजीवादी संकट आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों को लीलता जा रहा है। फलस्वरूप

साहित्य,कला,दर्शन, तथा विज्ञान में भी विकृतियां नज़र आ रही हैं। आज के साहित्य में विशेषकर निराशावादी, प्रतिक्रियावादी,रूढ़िवादी स्वभाव की बाढ़,तरह-तरह के आदर्शवादी मतों का प्रचार,रहस्यवाद के गड़े मुर्दों में पुनः जान डालने की कोशिश तथा वैज्ञानिक मतों को झुठलाने की मुहिम चल रही है। ऐसे हालात में क्या हम मीरा की तरह प्रेम दीवाने बनकर गरल पान करते रहेंगे या तुलसी की तरह -कोई नृप होहि हमहू का हानी की रट लगाए रहेंगे? आज जरूरी है साहित्य को नीतिशास्त्र ना बनाएं, कष्टों का रोना भी ना रोयें बल्कि साहित्य के मानदंडों को ऊंचा करना होगा जिससे वह समाज की अधिक मूल्यवान सेवा कर सके। हमें अपनी रुचि के अनुसार विषय चयन कर उस पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना होगा ताकि वह जीवन के प्रत्येक विभाग की आलोचना तथा विवेचना कर सके।

प्रेमचंद का मानना है- कि हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो,स्वाधीनता का भाव हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाईयों का प्रकाश हो ,जो हममें गति ,संघर्ष और बेचैनी पैदा करें, सुलाये नहीं ।वस्तुतः प्रगतिशील लेखक संघ ऐसी व्यवस्था चाहता है जिसमें मनुष्य दुखी ना हो। समाज में अन्याय, अत्याचार,शोषण ना हो। मनुष्य मुक्त हो, विवेकशील हो,अंधविश्वासों को छोड़कर वैज्ञानिक दृष्टि अपनाए । हरिशंकर परसाई जी कहते हैं- नारे कितने भी अच्छे हों, बेकार हैं यदि रचना के स्तर पर हम कमजोर पड़ते हैं। हमें बहुत जागृत रहना है। इसलिए बेचैन मानसिकता की जरूरत है। जागृत चेतना बेचैन रहती है ।प्रगतिशील लेखक संघ राजनीति और साहित्य की पारस्परिक संबंधों की मान्यता को भी स्वीकार करता है क्योंकि समाज में आधारित व्यवस्था में बदलाव आखिरकार राजनीतिक तरीकों से ही लाना है इसलिए नई कविता के युग प्रवर्तक मुक्तिबोध मानते थे- कि शोषण मुक्त समाज की स्थापना एवं मनुष्य की सत्ता का निर्माण करने का एकमात्र मार्ग राजनीति है,जिसका सहायक प्रगतिशील साहित्य है।

आज प्रगतिशील साहित्य के लेखकों का उत्तर दायित्व और बढ़ गया है जैसा कि सभी जानते हैं कि जोखिम उठाने का माद्दा सिर्फ प्रगतिशील लेखकों के पास है साहित्य में आज ऐसी ही तासीर की जरूरत है जो आदमी को अर्थ दे जीने की। आज साहित्य में समाज के प्रति संवेदना की जरूरत है। समाज में आमूलचूल परिवर्तन आवश्यक है यातनामयी, कारुणिक दृश्यों से भयाक्रांत होकर आंख ना मूंदे, चीत्कार के बीच कानो में रुई ठूंसने की बजाए आंख और कान खोलकर लेखन करें । कला और साहित्य समाज को बदलने के लिए हैं। निराश ना हो । देखिए,किसी ने क्या खूब लिखा है-

प्रेमचंद कैसे पैदा ना हो
इस कलम को तो कुदाल कीजिए?

आइए,अभिव्यक्ति के ख़तरे उठाने प्रतिबद्ध हों। खुलकर लिखते रहें। यह आमजन के हित में ही नहीं बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए भी ज़रूरी है। अंत में ,विश्व के जाने-माने लेखक वारंट व्हिटमेन का ये विचार -कि हमारा साहित्यिक नारा कला कला के लिए नहीं बल्कि कला समाज को बदलने के लिए हैं।इस नारे को बुलंद करना प्रत्येक प्रगतिशील साहित्यकार का कर्तव्य है ।

राम महिमा

राम का जीवन: वर्तमान समाज के लिए प्रेरक संदेश

डॉ.परविंदर शर्मा

अध्यक्ष एवं सहायक आचार्य, भगवान् श्री परशुराम जी पीठ, जगत गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, पटियाला

भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की परम्पराओं में अनेक पर्व और उत्सव हैं, जो न केवल धार्मिक आस्था के प्रतीक हैं, बल्कि जीवन जीने की कला और मूल्यों की शिक्षा भी प्रदान करते हैं। इन्हीं पर्वों में से एक है राम नवमी, जो भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। श्रीराम भारतीय जनमानस के लिए केवल एक धार्मिक पात्र नहीं हैं, बल्कि वे एक जीवित आदर्श हैं- एक मर्यादित राजा, आज्ञाकारी पुत्र, समर्पित पति, नीतिपरायण प्रशासक और सबसे बढ़कर धर्म के मार्ग पर अडिग रहने वाले मानव।आज के युग में, जब समाज विविध प्रकार की चुनौतियों से जूझ रहा है - नैतिक पतन, भ्रष्टाचार, पारिवारिक विघटन, सामाजिक असमानता और आध्यात्मिक खोखलेपन से ग्रस्त है- ऐसे में राम नवमी हमें यह अवसर देती है कि हम श्रीराम के जीवन से प्रेरणा लें और उन्हें एक मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करें। आज के समय में श्रीराम का जीवनः एक प्रेरणादायक आदर्श बन कर समाज को एक सही दिशा परदान कर सकता है। जिस की कुछ उदाहरण इस तरह मिलती है। राम को 'मर्यादा पुरुषोत्तम' कहा गया है। इसका अर्थ है- ऐसा व्यक्ति जो हर परिस्थिति में मर्यादा और धर्म का पालन करे। राजा होते हुए भी उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि माना और 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। आज के समाज में, जहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ प्राथमिकता बन गया है, राम का यह त्याग एक प्रेरणा है।राम ने अपने जीवन में माता-पिता की सेवा और आज्ञा का पालन कर आदर्श पुत्र का उदाहरण प्रस्तुत किया। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ उनका संबंध भाईचारे, प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। आज के समाज में परिवार टूटते जा रहे हैं, तो राम की पारिवारिक भावना हमें पुनः एक सूत्र में बांध सकती है।रामराज्य की कल्पना हर नागरिक की अभिलाषा होती है। राम ने अपने राज्य में सभी धर्म, जाति और वर्गों को समान रूप से सम्मान दिया। उनके शासन में न्याय, सुरक्षा, समृद्धि और धर्म की स्थापना थी। आज के राजनीतिक नेतृत्व को राम जैसे शासक से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है।राम का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। उन्होंने असत्य, अन्याय और अहंकार के प्रतीक रावण का संहार किया। यह संघर्ष आज के समाज को यह सिखाता है कि बुराई के विरुद्ध

संघर्ष करना ही धर्म है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विषम क्यों न हों।

आज के समाज के अन्दर राम नवमी का जे पवन अवसर अहम् भूमिका अदा करता है। जिस के संदेश से पुरे विशव के अन्दर सुख और समर्धि आ सकती है।आज की दुनिया में, जहाँ झूठ, फरेब, लालच और अन्याय आम हो गया है, राम नवमी का संदेश यह है कि सत्य, करुणा, और धर्म का मार्ग ही दीर्घकालीन समाधान है। श्रीराम के जीवन से यह स्पष्ट होता है कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंततः वही विजयी होता है। राम ने वनवास के दौरान विविध जातियों, वनवासियों, आदिवासियों और यहाँ तक कि पशु-पक्षियों के साथ भी प्रेमपूर्वक व्यवहार किया। उनके जीवन में समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति सम्मान का भाव था। आज के समय में, जब जातीय और सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहे हैं, राम का यह दृष्टिकोण समाज को एक सूत्र में बाँधने में सहायक हो सकता है।राम ने सीता के साथ सदा सम्मान और आदर का व्यवहार किया। रामायण में कई स्त्रियाँ- जैसे सीता, कौशल्या, सुमित्रा, शबरी, और अहिल्या- आदर्श नारी रूप में सामने आती हैं। आज जब नारी असुरक्षित महसूस करती है, तब राम नवमी का यह संदेश अत्यंत प्रासंगिक है कि नारी को देवी रूप में देखा जाए, न कि भोग की वस्तु के रूप में। हम कह सकते है कि भगवान् श्री परशुराम जी के दवरा नारी शक्ति अभियान को राम जी ने आगे दिशा दी थी जिस के चलते ही नारी का सामान होता रहा। राम का नेतृत्व नीतिपरायण, न्यायप्रिय और लोककल्याणकारी था। आज के नेताओं को राम के चरित्र से प्रेरणा लेकर राजधर्म का पालन, नैतिकता और पारदर्शिता के साथ शासन करना चाहिए।राम के वनवास काल में प्रकृति के साथ उनका तालमेल गहरा था। वे वृक्षों, नदियों, पर्वतों, और पशुओं के साथ प्रेमपूर्वक रहते थे। आज जब पर्यावरण संकट गंभीर होता जा रहा है, राम का यह दृष्टिकोण हमें प्रकृति के साथ सहजीवन का पाठ पढ़ाता है।

राम नवमी केवल श्रीराम के जन्म का उत्सव नहीं, बल्कि सत्य, त्याग, सेवा, और कर्तव्य के जन्म का प्रतीक है। यह पर्व हमें यह स्मरण कराता है कि समाज में कितनी भी समस्याएं हों, यदि हम राम जैसे आदर्शों को अपनाएं, तो समाधान संभव है।आज के समाज को श्रीराम के चारित्रिक गुणों की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है – मर्यादा, संयम, सेवा, कर्तव्य और करुणा। राम नवमी का पर्व हमें केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन प्रदान करता है। आइए, हम यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन को श्रीराम के आदर्शों के अनुरूप बनाएँगे, ताकि हम एक समरस, न्यायपूर्ण, और नैतिक समाज की ओर अग्रसर हो सकें।

फांसी दिवस पर

मंगल पांडे : 1857 की क्रांति का जनक

प्रमोद दीक्षित मलय

लेखक स्तम्भकार हैं।

29 मार्च, 1857। कलकत्ता से 22 किमी दूर भारत की सबसे बड़ी और प्लासी युद्ध के बाद सन् 1765 में स्थापित पहली सैन्य छावनी बैरकपुर छावनी में ईस्ट इंडिया कम्पनी की बंगाल इंफेंट्री रेजीमेंट की 34वीं वाहिनी के सिपाही सुबह नियमित परेड के लिए मैदान में वर्दी पहने अपनी बंदूकों सहित तैयार खड़े हैं। नायक के आदेश पर परेड आरम्भ हुई। सिपाही कदम से कदम और हाथ से हाथ मिलाते हुए निश्चित सीमा तक परेड करते हुए आ-जा रहे हैं। सिपाहियों की गर्दनें तनी हुई और सिर ऊंचे हैं। पूरी देह में रक्त नसों में दौड़ रहा है। सिपाहियों के मुख मण्डल शौर्य एवं पराक्रम से दीप्तिमान हैं। किंतु आज सैनिकों का भाव और व्यवहार बिल्कुल अलग सा है। लग रहा है कि जैसे उनके हृदयों में कुछ उबल रहा है। परेड को विश्राम दिया गया और सभी सिपाहियों को नये कारतूसों का वितरण शुरू हुआ। लेकिन यह क्या, एक सिपाही ने कारतूस लेने स्पष्ट मना कर दिया। वह बोला, 'इन कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी लगी है। हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारा धर्म भ्रष्ट होगा।' अन्य सिपाहियों ने भी साथ दिया। कारतूस वितरण करने वाले ने कड़क आवाज में पूछा, 'तुम्हारा नाम-परिचय क्या है?' वह युवा सिपाही उच्च स्वर में बोला, 'नाम मंगल पांडे। पिता दिवाकर पांडे, माता अभय रानी। जन्म तिथि 19 जुलाई, 1827 बलिया में। सेना में भर्ती सन् 1849 में।' इतना सुनकर कारतूस वितरण करने वाला अधिकारी काम बंद कर लेफ्टिनेंट बॉग के कक्ष की ओर बढ़ गया और सैनिक अपनी बैरकों की ओर।

हुगली नदी के सुरम्य प्राकृतिक तट पर स्थित ईस्ट इंडिया कम्पनी की बैरकपुर छावनी में उस दिन सुबह की इस घटना ने पूरे सैन्य अधिकारियों के कान खड़े कर दिए थे। समाधान हेतु उनमें विचार-विमर्श चल रहा था। इधर, सैनिक भी अपनी बैरकों में बैठे चर्बी वाले कारतूस प्रयोग न करने पर दृढ संकल्पित थे क्योंकि बंदूक की नली में कारतूस भरने से पहले उसका अगला सिरा दांत से काट बारूद नली में भरकर फिर कारतूस डालना होता था। गाय हिंदुओं के लिए पूज्या थी तो सुअर की चर्बी से मुस्लिम सैनिकों की भावना आहत थी। सैनिकों ने तय किया कि यदि अधिकारियों ने चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने का दबाव बनाया तो खुला विरोध करेंगे, बगावत होगी। मंगल पांडे के दिल-दिमाग में यह बात कुछ अधिक ही घर कर गई थी। उस शाम जब सूर्यदेव विश्राम हेतु पश्चिम के नील गगन के क्षितिज-पर्यंक पर गमन करने वाले थे, विहंग वृंद अपने नीड़ की ओर उड़ान भर रहा था, गायें रंभाती हुई बछड़ों को दुग्धपान कराने गोशाला की ओर दौड़ रही थीं, तभी उस गोधूलि बेला में मंगल पांडे भरी बंदूक लेकर बैरक से बाहर आया और साथी सिपाहियों को ललकारते हुए चर्बी युक्त कारतूस प्रयोग के विरोध हेतु बाहर निकलने का आह्वान किया। सिपाही बाहर आ गये। घटनाक्रम की

खबर अंग्रेजों के वफादार किसी सैनिक द्वारा नमक-मिर्च लगाकर तुरंत लेफ्टिनेंट बॉग तक पहुंची। नाफरमानी को बगावत समझ लेफ्टिनेंट बॉग झटपट घोड़े पर सवार हो सिपाहियों की ओर बढ़ चला। शीघ्र ही पहुंचकर उसने देखा कि तीस वर्षीय सिपाही मंगल पांडे साथी सिपाहियों को कारतूस नहीं लेने के लिए मना कर रहा है, सिपाहियों में आक्रोश है। रोष से चेहरे तमतमा उठे हैं। लेफ्टिनेंट बॉग समझ गया कि यह तो खुला विद्रोह है, फिर भी अंदर से भयभीत उसने साहस बटोर कर आदेश दिया, 'सिपाहियों ! बैरक में जाओ।' पर विरोध में एक साथ कई मुट्ठियां आकाश में तन गईं। बौखलाये बॉग की नजर नेतृत्व कर रहे सैनिक मंगल पांडे पर पड़ी और वह गरज कर बोला, 'तुम अपनी बंदूक और वर्दी जमा करो।' आदेश का कोई असर होता न देख, वह मंगल पांडे को पकड़ने को बढ़ा। किंतु मंगल पांडे ने फायर कर दिया। बॉग बाल-बाल बच गया, किंतु गोली घोड़े के पैर पर लगी और सवार सहित घोड़ा धराशायी हो गया। बॉग खड़ा हुआ और सिपाहियों को मंगल पांडे को पकड़ने का हुक्म दिया पर एक भी सिपाही आगे नहीं बढ़ा। क्रोधित लेफ्टिनेंट बॉग ने तलवार निकाल मंगल पांडे पर प्रहार किया। बचाव में मंगल पांडे ने भी तलवार से जोरदार हमला किया, बॉग के सीने से लहू की धार बह निकली। तब तक मेजर ह्यूसन अंग्रेज सैनिकों के साथ पहुंच गया जिसका स्वागत मंगल पांडे की बंदूक से निकली गोली ने किया। अब मंगल पांडे की तलवार का मुकाबला एक साथ दो तलवारों से हो रहा था। लेफ्टिनेंट बॉग और मेजर ह्यूसन खून से लथपथ थे पर तलवारें भांज रहे थे, कि तभी मंगल पांडे ने उछलकर तलवार का जोरदार प्रहार किया किंतु अंग्रेजों के वफादार सैनिक शेख पलटू ने मंगल पांडे की कमर पकड़ ली। तब तक अन्य अंग्रेज सैनिकों का जत्था निकट आ पहुंचा। अपने को घिरा देख मंगल पांडे ने आत्म बलिदान हेतु स्वयं पर गोली मार ली, वह घायल होकर मां भारती की गोद में गिर पड़े। अंग्रेज सैनिकों ने मंगल पांडे को बंदी बना लिया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। 6 अप्रैल, 1857 को कोर्टमार्शल हुआ और मंगल पांडे को मृत्युदंड दिया गया। फांसी की तारीख निश्चित की गई 18 अप्रैल। किंतु मेरठ, कानपुर , दिल्ली से आ रही बगावत की खबरों से परेशान अंग्रेजों ने तय तारीख से दस दिन पहले 8 अप्रैल, 1857 की प्रातः 5.30 बजे बैरकपुर छावनी में सिपाहियों के सामने घायल मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस दिन जब सूरज उगा तो अपनी किरणों का स्वर्णिम गुच्छ बलिदानी मंगल पांडे के चरणों में समर्पित कर अपनी श्रद्धाजलि दी, जिसने भारत की स्वतंत्रता के लिए पहली गोली चलाई थी। मंगल पांडे को फांसी के बाद सामूहिक सजा के तौर पर पूरी 34वीं रेजीमेंट को भंग कर दिया गया

मंगल पांडे की स्मृति में भारत सरकार ने 5 अक्टूबर, 1984 को 50 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया, जिसे कलाकार सी.आर.पाकरसी ने डिजाइन किया था। बैरकपुर में बना मंगल पांडे का ओजमय समाधि स्थल दर्शनार्थियों में देशभक्ति, त्याग एवं बलिदान का भाव भरते हुए देश के सर्वांगीण विकास का आह्वान कर रहा है।

सातवां पोषण पखवाड़ा 8 से 22 अप्रैल तक

बैतूल। व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से कुपोषण को कम करने के लिए पोषण अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष पोषण अभियान के तहत पोषण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है। इस पर सातवां पोषण पखवाड़ा 8 से 22 अप्रैल तक मनाया जाएगा। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा जीवन के प्रथम 1000 दिवस पोषण ट्रैकर में लाभार्थी मॉड्यूल को लोकप्रिय बनाने व्यापक प्रचार-प्रसार, समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन मॉड्यूल के माध्यम से कुपोषण का प्रबंध तथा बच्चों में मोटापे को दूर करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली को अपने पर बाल जैसे थीम पर केंद्रित विभिन्न गतिविधियों को आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। पोषण पखवाड़ा के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र सेक्टर, परियोजना एवं जिला स्तर की गतिविधियों में स्थानीय पोषण संसाधनों की को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, सामुदायिक जागरूकता और पोषण संवेदनशील कार्यक्रम जैसे आयोजन किए जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों में दैनिक गतिविधियों की तिथि वार थीम आधारित कैलेंडर तैयार किया गया है। सभी जिलों में पखवाड़ा के दौरान साइकिल रैली, पोषण रैली, प्रभात फेरी, गर्भवती महिलाओं और धात्री माता एवं किशोरी बालिकाओं के साथ पोषण ट्रैकर में हितग्राही मॉडल पर समूह चर्चा, कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य जांच, एनीमिया जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। पोषण पखवाड़ा के दौरान लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष, शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण, शहरी विकास सहयोग से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

आयुक्त महिला बाल विकास ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि पोषण पखवाड़ा के दौरान जिले में प्रत्येक स्तर पर इसका प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि 8 अप्रैल को पोषण पखवाडा का शुभारंभ स्थानीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाये। और कार्यक्रम में उपस्थित सभी जन सामान्य को पोषण शपथ भी दिलाई जाए।

बच्चों को भोजन के साथ वितरित की पाठ्य सामग्री

बैतूल। इंदिरा नगर, जय प्रकाश वार्ड स्थित पंचशील निःशुल्क कोचिंग क्लासेज में जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए प्रेरणादायी पहल की गई। इस नेक कार्य में प्रोफेसर डॉ. अर्चना सोनारे, डॉ. पीआर सोनारे, डॉ. सुखदेव डोंगरे और शिक्षिका भागरती डोंगरे ने मिलकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान

लाने का कार्य किया। इन समाजसेवियों द्वारा बच्चों को पढ़ाई के लिए आवश्यक निशुल्क सामग्री वितरित की गई। साथ ही बच्चों को घर पर बना हुआ स्वादिष्ट भोजन भी दिया गया, जिससे वे आत्मीयता और अपनापन महसूस कर सकें। शिक्षा के इस अभियान को और अधिक मानवीय बनाते हुए बच्चों को चप्पल भी प्रदान की गई, ताकि वे नंगे पैर न रहें और स्वाभिमान के साथ स्कूल जा सकें। इस मौके पर बच्चों को शिक्षा के महत्व को समझाते हुए उन्हें प्रेरित भी किया गया। उन्हें बताया गया कि पढ़ाई से ही जीवन में बदलाव संभव है और हर बच्चा देश का भविष्य है। इस प्रेरणादायक कार्य में जीआर पटेल, पुष्पा पटेल, रमाशंकर आवलेकर, कमला आवलेकर, मिलन सिंगारे और कमला जी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने अपनी सेवाएं देकर बच्चों के लिए यह आयोजन सफल बनाया।

बैतूल की रौनक देशमुख बनीं डॉक्टर

एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर से पास की एमबीबीएस की परीक्षा

बैतूल। जिले की प्रतिभाशाली छात्रा कुमारी रौनक देशमुख ने शासकीय महात्मा गांधी मेमोरियल

मेडिकल कॉलेज, इंदौर से एमबीबीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की है। कुमारी रौनक देशमुख शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल रही हैं। कक्षा 10वीं में उन्होंने 10 सीजीपीए अंक प्राप्त किए थे और कक्षा 12वीं की परीक्षा उन्होंने 95 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की थी। 12वीं में बायोलॉजी ग्रुप से उन्होंने जिले में टॉप किया था। रौनक के पिता अनिल देशमुख और माता हर्षा देशमुख दोनों ही स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं। माता-पिता की सेवा भावना से प्रेरित होकर रौनक ने भी डॉक्टर बनने का सपना देखा और उसे साकार कर दिखाया। एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त करने के बाद अब रौनक देशमुख अपने ही जिले में रहकर समाज की सेवा करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही हैं।

करों की वसूली को लेकर नपा का अभियान रहा सुस्त, नपा की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा असर

वित्तीय वर्ष 2024-25 में नपा कर पाई 65 फीसदी करों की वसूली, पिछले साल से एक प्रतिशत अधिक

संजय द्विवेदी, बैतूल। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 34 प्रतिशत शहरवासियों ने टैक्स जमा नहीं किया है। अब उन्हें विगत और चालू वित्तीय वर्ष यानि दोनों वर्ष का टैक्स जमा करना होगा। टैक्स वसूली को लेकर नगरपालिका ने भारी भरकम प्रयास भी किया। लेकिन नपा वित्तीय वर्ष 2024-25 में महज 65.51 प्रतिशत ही वसूली कर पाई है। यह वसूली गत वर्ष की अपेक्षा एक प्रतिशत ही बढ़ पाई है। दरअसल राजस्व अमले ने दावा किया था कि वसूली का प्रतिशत 80 को पार कर जाएगा, लेकिन नपा कर्मचारियों का अनुमान फिसड्डी साबित हुआ। नपा कुल 10 करोड़ 21 लाख में से 6 करोड 69 लाख ही राजस्व वसूल कर पाई है। नपा के वसूली अभियान में फरवरी-मार्च में ही तेजी आती है, लेकिन यह कवायद भी अधिक वसूली के लिए फायदा नहीं कर पाई। यही वजह है कि राजस्व वसूली का लक्ष्य नपा चाहकर भी पूरा नहीं कर पाई है। बता दे कि सामान्य तौर पर किसी भी नपा की वित्तीय स्थिति राजस्व विभाग पर टिकी रहती है। बताया जाता है कि सभी करों का भुगतान आने के बाद यह राशि नपा विकास कार्यो पर खर्च करती है। नपा का बजट भी राजस्व वसूली पर निर्भर करता है।

वर्ष 2024-25 में राजस्व वसूली की स्थिति

कर कुल	मांग	कुल वसूली
संपत्ति कर	37078418	34643739
समेकित कर	8581354	4105853
सामान्य जलकर	801761	617012
जल शुल्क	27987191	11367570
दुकान/भवन किराया	8350753	3870289
शिक्षा उपकर	9076274	5615093
नगरीय विकास उपकर	10274026	6694189
योग	102149777	66913745

अब करदाताओं भरना होगा दोनों वर्ष का टैक्स - चालू वित्तीय वर्ष में यदि टैक्स जमा नहीं किया जाता है तो तो करदाताओं को आगामी वित्तीय वर्ष में दोगुना यानि दोनों वर्ष का टैक्स जमा करना होगा। बताया गया कि यह संशोधित प्रावधान पिछले वित्तीय वर्ष में ही किया गया है। देखा जाए तो इस वित्तीय वर्ष में नगरपालिका को डिमांड से करीब 3.52 करोड़ रुपए कम मिले है। बताया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में नगरपालिका की कुछ डिमांड 10 करोड़ 21 लाख 49 हजार 777 थी। जिसके विरूद्ध नगरपालिका महज 6 करोड़ 69 लाख 13 हजार 745 रुपए ही वसूल सकी है। जबकि 3 करोड़ 52 लाख 36 हजार से अधिक राशि शहरवासियों को बकाया है। इस वित्तीय वर्ष में नगरपालिका की महज 65.51 प्रतिशत ही राजस्व वसूली हो सकी है।

जल शुल्क वसूली में भी नपा पिछड़ी

जल शुल्क की वसूली में हर साल की तरह इस साल भी नगरपालिका पिछड़ गई है। शहर में जलशुल्क की डिमांड 2 करोड़ 79 लाख 87 हजार 191 रुपए थी। जिसके विरूद्ध नगरपालिका 1 करोड़ 13 लाख 67 हजार 570 रुपए की वसूल कर पाई है। जबकि 1 करोड़ 66 लाख 19 हजार 621 रुपए अब भी शहरवासियों पर बकाया है। जलकर की शतप्रतिशत वसूली नहीं हो पाने के कारण नगरपालिका पर पेयजल सप्लाई को वित्तीय भार बढ़ रहा है। इस वजह से नगरपालिका को जलशुल्क की दर 150 रुपए प्रतिमाह करना पड़ता है। नगरपालिका में जलशुल्क वसूली का सबसे कम 40 प्रतिशत रहा है।

नपा की वित्तीय स्थिति पर पड़ रहा असर

शहर के लोग जागरूक होने के बावजूद विभिन्न करों का भुगतान करने में लेटलतीफी करते है। इसका खामियाजा नपा की वित्तीय स्थिति पड़ता है, जबकि शहर के 33 वार्डों में अलग-अलग दिनों संपत्ति कर वसूली के लिए अभियान भी चलाया जाता है और करो की वसूली के लिए टीम भी बनाई थी। नपा ने शिविर भी लगाए, लेकिन अपेक्षाकृत वसूली नहीं हो पाई। वैसे नपा सालभर करों की वसूली करती है, लेकिन वित्तीय वर्ष की समाप्ति में करों की वसूली का अभियान तेज कर देती है। जागरूक नागरिकों का कहना है कि राजस्व अमले के पीछे राजस्व वसूली के अलावा कई अन्य काम भी सौंपे जा रहे हैं। इस वजह राजस्व वसूली का काम पिछड़ जाता है।

इनका कहना है -

2024-25 में जिन्होंने टैक्स जमा नहीं किया है, उन्हें दोनों वर्ष यानी बकाया और चालू वित्तीय वर्ष का टैक्स देना होगा। बकाया राशि पर अलग से सरचार्ज लगेगा। वित्तीय वर्ष में 65.51 प्रतिशत वसूली हुई है।

- **ब्रजगोपाल परते,** वरिष्ठ राजस्व अधिकारी, नपा बैतूल

समस्या ग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल समस्याओं का करें उचित निराकरण

बैतूल। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति संबंधी समस्या के समाधान तथा नगर में अवैध अतिक्रमण को हटाने के उद्देश्य से सोमवार को कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के साथ विधायकगणों की एक महत्वपूर्ण बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक के दौरान कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने जानकारी दी कि जिले में कुल 96 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां पेयजल की गंभीर समस्या है। इन स्थानों पर शीघ्र ही बोरिंग कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। बोरिंग कार्यों को विभागीय, सांसद एवं विधायक निधि के माध्यम से कराया जाएगा, ताकि त्वरित समाधान हो सके। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जहां बोरिंग पर प्रतिबंध है उन क्षेत्रों के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिससे प्रतिबंध हटाकर राहत पहुंचाई जा सके।

विधायकों ने भी रखे सुझाव- बैठक में बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल, आमला विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे, भैंसदेही विधायक महेंद्र सिंह चौहान, मुलताई विधायक चंद्रशेखर देशमुख, घोड़ाडोंगरी विधायक श्रीमती गंगाबाई उईके ने समस्या ग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल समस्या के निराकरण के लिए अधिकारियों से चर्चा की और अपने सुझाव दिए। बैठक में कलेक्टर ने नल-जल योजना के अंतर्गत अधूरे कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए। उन्होंने कहा कि जहां नल-जल योजनाएं बंद पड़ी हैं, वहां संबंधित ठेकेदारों के माध्यम से कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए। ऐसे ठेकेदार जो अनावश्यक रूप से कार्य में विलंब कर रहे हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अवैध अतिक्रमण पर कड़ा रूख- बैठक में नगर में अवैध अतिक्रमण पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने नगर पालिका, राजस्व और पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि नगर की यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए 114 वैध गुमठियों के अतिरिक्त अन्य गुमठियों को तत्काल हटाया जाए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण से आमजन को परेशानी होती है और यह नगर की सौंदर्यता को भी प्रभावित करता है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्रामीण अंचलों में पेयजल संकट से निपटने के लिए कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों में टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

जीवन जीने की नई राह दिखा रहा हार्टफुलनेस ध्यान केंद्र

रीजनल को-ऑर्डिनेटर की मौजूदगी में शुरू हुआ ध्यान साधना का नया अध्याय

बैतूल। रामनवमी के अवसर पर बैतूल के रानीपुर रोड स्थित वृंदावन नगर कॉलोनी में हार्टफुलनेस ध्यान केंद्र का शुभारंभ किया गया। यह शुभारंभ रीजनल कोऑर्डिनेटर गजेंद्र गौतम, प्रशिक्षक एवं आईजी पुलिस प्रशासन भोपाल रूचिवर्धन मिश्रा, आशीष श्रीवास, रोहित बघेल, बीआर गभाडे, कमल नयन अग्रवाल, अशोक कुमार माहोरे, डॉ. आनंद मालवीय, हेमंत चिल्हाटे, आशीष पचौरी, तूलिका पचौरी, डॉ. शिशिर वाडेकर, राजेंद्रसिंह परिहार, दीपक राजपूत, अभिषेक भदौरिया तथा अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर गजेंद्र गौतम ने बताया कि हार्टफुलनेस ध्यान एक प्राचीन राजयोग पद्धति पर आधारित है, जो जीवन जीने की कला सिखाता है। यह पद्धति दिव्य योग ऊर्जा, प्राण आहुति के माध्यम से शुद्ध हृदय को केंद्र में रखकर ध्यान का अभ्यास कराती है। इसके चार मुख्य अभ्यास हैं जो मन को स्थिर, तनावमुक्त और भयमुक्त बनाते हैं। यह अभ्यास पूर्णत- निशुल्क है और सभी जाति-धर्म के लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध है।

हृदय से हृदय तक पहुंचने वाली ऊर्जा का माध्यम- श्रीमती रूचिवर्धन मिश्रा ने कहा कि हार्टफुलनेस ध्यान एक जीवनशैली है जो हृदय पर केंद्रित होकर जीने की प्रेरणा देती है। यह साधना प्रेम, शांति और स्थिरता की स्वाभाविक स्थिति को अनुभव करने में सहायक होती है। हार्टफुलनेस ध्यान की विशेषता इसकी सूक्ष्मता और सरलता है, जो प्रत्येक व्यक्ति को उनके हृदय में उपस्थित प्रकाश और प्रेम से जोड़ती है। उन्होंने बताया कि प्राण आहुति युक्त ध्यान, हृदय से हृदय तक पहुंचने वाली ऊर्जा का माध्यम है।

रिलैक्सेशन तकनीक का अभ्यास कराया- कॉन्टैक्टर कमल नयन अग्रवाल द्वारा वृंदावन नगर कॉलोनी में हार्टफुलनेस ध्यान केंद्र हेतु एक हॉल पूर्णत- निशुल्क उपलब्ध कराया है। यह केंद्र सभी नागरिकों के लिए प्रतिदिन ध्यान हेतु खुला रहेगा, जहां कोई भी व्यक्ति आकर निशुल्क साधना कर सकता है। शुभारंभ कार्यक्रम तीन सत्रों में संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 300 लोगों ने भाग लिया। प्रथम सत्र में हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन तकनीक का अभ्यास कराया गया। दूसरे सत्र में रिलैक्सेशन के बाद ध्यान कराया गया और ध्यान के बाद प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए।

तनाव, चिंता और भय से मिलेगी मुक्ति- तीसरे सत्र में हार्टफुलनेस की सफाई प्रक्रिया से अवगत कराया गया, जिसमें बताया गया कि कैसे नियमित अभ्यास से व्यक्ति अपने अंदर जमा हुई नकारात्मक छापों, तनाव, चिंता और भय से मुक्त हो सकता है। कार्यक्रम के अंत में रात्रि विश्राम से पूर्व सामूहिक प्रार्थना कराई गई, जिसमें प्रार्थना के महत्व और उसके प्रभावों पर प्रकाश डाला गया। समापन अवसर पर मां शारदा सहायता समूह की सदस्य शैरन बिहार, ए. दीप मालवीय, हिमांशु सोनी, प्रदीपन संस्था से रेखा गुजरे, जन अभियान परिषद से जयश्री देशमुख एवं अन्य सहयोगियों ने श्रीमती रूचिवर्धन मिश्रा का पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मान किया।

जिले में अवैध खनिज परिवहन एवं भण्डारण पर बड़ी कार्रवाई, एक डंपर एवं तीन ट्रैक्टर जब्त

खनिज विभाग ने दो दिनों में की सख्त कार्रवाई, 3.45 लाख रुपये का जुर्माना प्रस्तावित

बैतूल। जिले में अवैध खनिज परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध खनिज विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए बीते दो दिनों में विभिन्न क्षेत्रों से एक डम्पर और तीन ट्रैक्टर जप्त किए हैं। यह कार्रवाई कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशानुसार खनिज विभाग द्वारा की गई, जिसमें विभागीय अमले के साथ आकस्मिक निरीक्षण किया गया। खनिज अधिकारी मनीष पालेवार ने बताया कि 4 अप्रैल 2025 को बैतूल जिले के तहसील आमला के ग्राम बोथिया ब्राम्हणवाड़ा आरएमसी प्लांट एवं डामर प्लांटों के प्लांट संचालक द्वारा प्लांट संचालन के लिए क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड छिंदवाड़ा से जल एवं वायू की बिना सम्मति प्राप्त किये एवं खनिजों के भंडारण के लिए बिना भण्डारण अनुज्ञप्ति लिये अवैध रूप से खनिजों का भण्डारण किया जा रहा था। क्षेत्रीय अधिकारी, मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड छिंदवाड़ा से पत्र के पालन में सहायक खनि अधिकारी एवं खनि निरीक्षक बैतूल द्वारा खनि अमले के साथ तहसील आमला के गाम ब्राम्हणवाड़ा में स्थित निजी भूमि ख.क. 296/2, रकबा 3.949 हे. के अंश भाग पर संचालित

आरएमसी एवं डामर प्लांटों की जांच की गई। मौके पर प्लांट के समीप गिट्टी, डस्ट की अवैध रूप से भंडारित मात्रा 96 घन मीटर पाई गई जिसे जप्त किया जाकर प्लांट संचालक आशीष पिता हरेराम अग्रवाल, निवासी दुर्गा चौक घोड़ाडोंगरी की सुपुर्दगी में दिया गया। मौका जांच अनुसार मध्यप्रदेश खनिज अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण का निवारण नियम 2022 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अर्थदण्ड राशि 3 लाख 45 हजार 600 रुपए प्रस्तावित की गई है।

आठनेर, आलमपुर और बगडोना में अवैध परिवहन पर की कार्रवाई- खनिज अधिकारी मनीष पालेवार ने बताया कि 5 अप्रैल 2025 को तहसील आठनेर में खनिज रेत का अवैध परिवहन करते हुए वाहन डम्पर क्रमांक आरजे 21 जीए 9412 को खनिज नियमों के तहत जप्त कर पुलिस थाना आठनेर की अभिरक्षा में रखा गया। इसी क्रम में तहसील चिचोली के ग्राम आलमपुर में खनिज रेत का अवैध परिवहन करते हुए वाहन ट्रैक्टर सोनालिका बिना नम्बर को खनिज नियमों के तहत जप्त कर पुलिस थाना चिचोली की अभिरक्षा में रखा गया एवं तहसील घोड़ाडोंगरी के ग्राम बगडोना में खनिज मुरूम का अवैध परिवहन करते हुए वाहन ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 48 एए 0265 को खनिज नियमों के तहत जप्त कर पुलिस चौकी घोड़ाडोंगरी की अभिरक्षा में रखा गया। इसी प्रकार 7 अप्रैल 2025 को तहसील बैतूल के ग्राम नाहिया में खनिज रेत का अवैध परिवहन करते हुए वाहन ट्रैक्टर सोनालिका को जप्त कर पुलिस चौकी बोड़खी आमला की अभिरक्षा में रखा गया है। उक्त सभी प्रकरणों पर अवैध भण्डारणकर्ता, परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध मध्यप्रदेश खनिज अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण का निवारण नियम 2022 के तहत अर्थदण्ड की राशि प्रस्तावित कर प्रकरण न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल में प्रस्तुत किया जा रहा है।

विश्व स्वास्थ्य दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर मातृ-शिशु और वृद्धजनों की जांच कर दी गई स्वास्थ्य सेवाएं

बैतूल। हर साल 7 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व स्वास्थ्य दिवस को इस वर्ष स्वस्थ शुरुआत, आशाजनक भविष्य थीम के साथ चिचोली विकासखंड में हर्षोल्लास और स्वास्थ्य जागरूकता के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश अतुलकर ने बताया कि इस दिवस का उद्देश्य आमजन में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें स्वस्थ जीवनशैली के लिए प्रेरित करना होता है। कार्यक्रम के दौरान चिकित्सा अधिकारी डॉ. महेश चौहान, बीईई एवं बीपीएम अनिल कटारे, बीसीएम विनीत आर्य तथा एमटीएस पंकज डोंगरे ने उपस्थित जनसमूह को मातृ एवं नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की महत्ता पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों की समय-समय पर जांच और देखभाल अत्यंत आवश्यक है, जिससे उनकी सेहत उत्तम बनी रह सके और भविष्य में किसी जटिलता से बचा जा सके। इस आयोजन के दौरान नीलेश सूर्यवंशी, विवेक नागले, गजराज रघुवंशी, राजकुमार यादव, कविता दरवाई, डी.टाटीसार, राजेश धुर्वे, रामरूप कैन, आकाश साहू सहित स्वास्थ्य विभाग का समस्त कार्यालयीन स्टाफ उपस्थित रहा। सभी ने स्वास्थ्य जागरूकता में सक्रिय सहभागिता दी। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अंतर्गत चिचोली विकासखंड के समस्त हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर विशेष जांच शिविर लगाए गए। इनमें माताओं, शिशुओं और वृद्धजनों की बीपी, शुगर सहित अन्य स्वास्थ्य जांच की गई। इस अवसर पर आमजन को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराने की सलाह दी गई। इस स्वास्थ्य आयोजन के माध्यम से चिचोली ने स्वस्थ शुरुआत की और एक मजबूत कदम बढ़ाया, जो आशाजनक भविष्य की नींव बनेगा।

सरोकार

डॉ. चन्दर सोनाने

लेखक मप्र जनसंपर्क के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं।

मध्यप्रदेश में 4 लाख 87 हजार पद खाली, बेरोजगारों का इंतजार

मध्यप्रदेश में अखिल भारतीय सेवा, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कुल 12,09,321 पद स्वीकृत है। इन पदों में से केवल 7,21,412 पद ही भरे हैं। इस प्रकार प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के कुल 4,87,909 पद वर्षों से खाली पड़े हुए हैं। इस प्रकार प्रदेश में कुल स्वीकृत पदों में से केवल 59.65 प्रतिशत पद ही भरे हुए हैं। कुल स्वीकृत पदों में से 40.35 प्रतिशत पद खाली पड़े हुए हैं। बेरोजगार वर्षों से इन खाली पदों की ओर आस भरी निगाहों से देख रहे हैं। किन्तु उन्हें निराशा ही मिल रही है।

मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग द्वारा डॉ. बी.आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंस महू को मध्यप्रदेश में पिछड़े वर्ग के आँकड़ों की रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया था। महू के विशेषज्ञों ने मध्यप्रदेश के 69 सरकारी विभागों के आँकड़ों का विश्लेषण करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की थी। उसने यह रिपोर्ट तैयार कर मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग को एक साल से अधिक समय से दे दी है। उस रिपोर्ट में मध्यप्रदेश में विभिन्न श्रेणियों में कुल स्वीकृत पद और रिक्त पदों की जानकारी भी है। इसके साथ ही रिपोर्ट में कुछ स्वीकृत पदों में से कुल भरे पदों की जानकारी के साथ ही सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनूसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की विस्तृत जानकारी भी शामिल की गई है।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर मध्यप्रदेश में अखिल भारतीय सेवा के कुल 1,258 पद स्वीकृत है। इनमें से मात्र 625 पद ही भरे हुए है। भरे पदों से अधिक 633 पद खाली पड़े हुए हैं। इस प्रकार आधे से अधिक 50.31 प्रतिशत पद खाली पड़े हुए हैं। प्रथम श्रेणी के कुल स्वीकृत पद 16,846 में से केवल 7,840 पद ही भरे हुए हैं। भरे पदों से अधिक 9,006 पद खाली पड़े हुए हैं। इस श्रेणी में भी आधे से अधिक 53.46 प्रतिशत पद खाली रखे हुए हैं। इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी के कुल 1,28,032 स्वीकृत पदों में से केवल 57,696 पद ही भरे हैं। इस श्रेणी में भी आधे से अधिक 70,336 पद खाली पड़े हैं। यह खाली पदों का 54.93 प्रतिशत है।

इसी प्रकार तृतीय श्रेणी के प्रदेश में कुल 9,21,631 पद स्वीकृत है। इस श्रेणी में 5,76,549 पद भरे हुए हैं। इस प्रकार इस श्रेणी में 3,45,082 पद खाली पड़े है। यह खाली पदों का 37.44 प्रतिशत है। इसी तरह चतुर्थ श्रेणी के कुल 1,41,554 पद स्वीकृत हैं। इसमें कुल 78,702 पद भरे हुए हैं। इस श्रेणी में 62,852 पद खाली पड़े हुए हैं। यह स्वीकृत पदों में से खाली पदों का कुल प्रतिशत 44.40 है। उक्त आँकड़े के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि अखिल भारतीय सेवा, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के कुल स्वीकृत पदों में से आधे से अधिक पद भी भरे ही नहीं गए हैं। इन उक्त तीनों श्रेणियों में खाली पदों का प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक है। यह अत्यन्त दुखद है। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद जरूर 50 प्रतिशत से अधिक भरे हुए है। किन्तु इसमें भी खाली पदों की संख्या हमें निराश करती है।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में बेरोजगारी का तेजी से बढ़ता हुआ आंकड़ा चैंकाने वाला है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में साल 2024 में जुलाई के समय 25 लाख 82 हजार बेरोजगार थे। जबकि दिसंबर में ये संख्या बढ़कर 26 लाख 17 हजार हो गई। लेकिन मार्च 2025 में ये आंकड़ा 29 लाख 36 हजार तक पहुंच चुका है। बेरोजगारों की बढ़ती हुई जनसंख्या निःसंदेह चिंताजनक है।

मध्यप्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान की सरकार ने अनेक बार ये घोषणा की थी कि सरकारी नौकरियों में 1 लाख पद भरे जायेंगे। किन्तु उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कभी एक लाख पद भरे ही नहीं गए। इसी प्रकार वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी अनेक बार ये घोषणा की कि प्रदेश में 1 लाख बेरोजगारों को नौकरियां दी जायेगी, किन्तु बेरोजगार अभी भी उन नौकरियों का इंतजार ही कर रहे हैं। प्रदेश में अखिल भारतीय सेवा, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कुल 4,87,909 पद खाली पड़े हुए हैं। तब राज्य सरकार 1 लाख पदों को भरने की बात किस आधार पर कर रही है। राज्य सरकार को शीघ्र प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के सभी खाली पदों को भरने का महाअभियान शुरू करना चाहिए। यह सब योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए, तभी बेरोजगारों के साथ न्याय हो सकेगा। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एक विशेष विजन रखने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते है। उनसे अपेक्षा है कि वे बेरोजगारों के इंतजार को समाप्त करेंगे।

हिन्दू दो नहीं, चार बच्चे पैदा करें

अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने की अपील

उज्जैन (नप्र)। चैत्रनवरात्र के मौके पर उज्जैन पहुंचे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने हिन्दू समाज से अपील की है कि वे तीन से चार बच्चे पैदा करें और उनमें से एक को संत बनने के लिए प्रेरित करें, ताकि सनातन धर्म और देश की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

रविंद्र पुरी महाराज ने कहा-आज अधिकतर हिन्दू सिर्फ दो बच्चों पर रुक जाते हैं। यदि सभी ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में संतों की संख्या कम हो जाएगी। इसलिए हिन्दू परिवारों को कम से कम चार संतानें उत्पन्न करनी चाहिए, जिनमें से एक को संन्यास के मार्ग पर चलने के लिए तैयार किया जाए।उन्होंने दावा किया कि देशभर से भक्त उनके पास फोन कर रहे हैं, जो अपने बच्चों को संत बनाना चाहते हैं। महाराज का कहना है कि यह धर्म और राष्ट्र दोनों के हित में है।

तेजस्वी का सपना, अब नहीं होगा पूरा- बिहार की राजनीति पर बोलते हुए रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि तेजस्वी यादव भले ही मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हों, लेकिन अब उनका यह सपना पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि बिहार में अगली सरकार भाजपा की ही बनेगी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। चारा घोटाले समेत पुराने मामलों की फिर से जांच शुरू हो चुकी है। आने वाला समय उनके लिए और कठिन हो सकता है। रविंद्र पुरी महाराज बीते तीन दिनों से उज्जैन में हैं और बड़नगर रोड स्थित निरंजनी अखाड़े में कन्या पूजन और भंडारे के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने बड़ी संख्या में जुटे साधु-संतों और श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरण भी कराया।

अधिकारियों को अपने अधिकारों की जानकारियां होना चाहिए : गुलशन बामरा

भोपाल(नप्र)। प्रमुख सचिव जनजाति श्री गुलशन बामरा ने कहा कि अधिकारियों को अपने अधिकारों के साथ अपने से वरिष्ठ अधिकारी के अधिकारों की भी जानकारियॉ होना चाहिए। प्रमुख सचिव श्री बामरा सोमवार को प्रशासन अकादमी में आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों की दो दिवसीय कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनजातीय वर्ग के 22 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति वर्ग के 16 प्रतिशत लोग निवास करते हैं। हमारी जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है, जब प्रदेश की कुल जनसंख्या के एक तिहाई से अधिक लोगों के विकास और उन्नति का दायित्व हमें सौंपा गया हो। इस अवसर पर आयुक्त श्री श्रीमन शुक्ल एवं आयुक्त सुश्री वंदना वैद्य भी उपस्थित थे।

संभागीय आयुक्त, सहायक आयुक्त एवं जिला संयोजक जनजातीय कार्य एवं अधिसूचना जाति कल्याण विभाग की दो दिवसीय प्रशिक्षण सह-उन्मुखीकरण कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों के विभागीय प्रशिक्षण सत्र के प्रथम दिन प्रमुख सचिव श्री बामरा ने अधिकारियों से उनके स्थापना संबंधी दैनंदिनी कार्य, जिसमें शासकीय सेवा में अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रशासन संबंधी कार्य जिसमें नियुक्ति, पदस्थापना, अनुकंपा नियुक्ति, गोपनीय चरित्रावली पेंशन प्रकरणों में आने वाली समस्याओं के निराकरण पर अधिकारियों से सवाल जबाव भी किए।

विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुख्यमंत्री निवास में सौजन्य भेंट की।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में प्रदेश के 16 नगर निगमों के महापौर की बैठक आज मंत्रालय में हुई।

शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि व्यक्तित्व का समग्र विकास होना चाहिए : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल के तृतीय दीक्षांत समारोह में हुए शामिल

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि विश्वविद्यालय महापुरुषों के निर्माण की फैक्ट्री होते हैं और शिक्षकगण इन संस्थाओं के कुशल कारीगर होते हैं। उन्होंने श्री रवींद्रनाथ टैगोर के उद्धरण का उल्लेख करते हुए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि व्यक्तित्व का समग्र विकास होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल के तृतीय दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि अपने ज्ञान का प्रयोग समाज के उत्थान में करें। केवल व्यक्तिगत सफलता ही नहीं, समाज और देश के विकास में भी भागीदारी आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि बड़े पद पर पहुँचने के बाद ही असली कार्य प्रारंभ होता है। अपने योगदान से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करें।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे राष्ट्र के तीव्र विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि देश अधोसंरचना, आर्थिक समृद्धि, और शिक्षा के क्षेत्र में

अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। उन्होंने वर्ष 2047 तक भारत को विश्वगुरु बनाने के संकल्प को दोहराया और कहा कि 'स्किल, स्केल और स्पीड' के तीन स्तंभों पर काम किया जा रहा है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कथन को उद्धृत करते हुए कहा कि 'धरती से दौलत निकालनी होगी'- इस विचारधारा को मूर्त रूप देते हुए 'नदी जोड़ो परियोजना' के माध्यम से कृषि क्षेत्र में नव युग की शुरुआत हो रही है।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि आज युवाओं के पास विकास के बहुत अवसर हैं। इन अवसरों का लाभ उठायें। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहें और अपनी ऊर्जा का सदुपयोग स्वयं, समाज, देश और विश्व के कल्याण के लिये करें। उन्होंने कहा कि समाज युवाओं की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहा है और युवाओं को इस भरोसे पर खरा उतरना होगा।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की दीक्षांत समारोह स्मारिका तथा 'कंप्यूटर एक परिचय' पुस्तक के 41वें संस्करण का विमोचन भी किया। समारोह में रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री संतोष चौबे, कुलगुरु डॉ. आर.पी. दुबे, इसरो के वरिष्ठ एयरोस्पेस वैज्ञानिक श्री राधाकांत पाढ़ी सहित अनेक गणमान्य नागरिक, शिक्षकगण एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

स्कूल शिक्षा विभाग का एजुकेशन पोर्टल-3.0

शत प्रतिशत नामांकन के लिये पोर्टल के माध्यम से किये जा रहे हैं प्रयास

भोपाल (नप्र)। स्कूल शिक्षा विभाग में अकादमिक एवं प्रशासनिक कार्यों के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग तथा परिणामों की समीक्षा के लिये डिजिटल प्लेटफार्म तैयार किया गया है। इस प्लेटफार्म पर विभिन्न स्तरों पर जानकारी की त्वरित उपलब्धता तथा उनके आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही की व्यवस्था की गयी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस वर्ष एक अप्रैल, 2025 को एजुकेशन पोर्टल-3.0 शुरू किया है।

विद्यार्थी प्रवेश प्रणाली- प्रदेश में एक अप्रैल से नवीन अकादमिक सत्र में सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में प्रवेश की कार्यवाही एजुकेशन पोर्टल-3.0 पर की जा रही है। इसके लिये स्टूडेंट डायरेक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया गया है। पोर्टल पर कक्षा-1 में संभावित पात्र विद्यार्थियों की सूची संबंधित शाला को उनके ग्राम और बसाहट के अनुसार प्रदर्शित की गई है। इस सुविधा से पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश कराने में सुलभता होगी। शाला प्रभारी द्वारा सूची के अनुसार पालकों से सम्पर्क कर विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाया जायेगा। इस वर्ष नवीन पोर्टल पर सभी शालाओं एवं उनमें पदस्थ शिक्षकों को लॉग इन आईडी दी गई है। शाला प्रवेश के समय दस्तावेज के अभाव में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश से वंचित नहीं रखा जायेगा।

कक्षोन्नति- पूर्व से शालाओं में दर्ज विद्यार्थियों की अगली कक्षा में प्रवेश के लिये विगत वर्ष 2024-25 में कक्षा-1 से 8 तक की शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की जानकारी प्रदर्शित की गई है। शिक्षक द्वारा परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की जानकारी पोर्टल पर संबंधित शिक्षक या स्कूल की आईडी से चिन्हित की जायेगी। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के समक्ष पास अथवा फेल की प्रविष्टि करते हुए प्रतिशत अंकित करने पर विद्यार्थी अगली कक्षा में पोर्टल पर स्वतः ही प्रवेशित हो जायेंगे। प्रदेश की ऐसी प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में जहाँ अगली कक्षा क्रमशः 6 और 9 उपलब्ध नहीं हैं, ऐसी स्थिति में कक्षा-5, 8 एवं कक्षा-10वीं के विद्यार्थियों को पूर्व की शाला के प्रधानाध्यापक, प्राचार्य विद्यार्थियों एवं पालकों से चर्चा कर समीप शाला में कक्षा-6, 9 एवं कक्षा 11 में ऑनलाइन प्रवेशित करायेंगे। संबंधित शाला जहाँ प्रवेश होना है, ऐसे विद्यार्थियों की सूची को समीपस्थ विद्यालय के शिक्षकों-शालाओं के लॉगइन में होगी। वरिष्ठ शाला के प्राचार्य भी विद्यार्थी पर क्लिक कर उसे अपनी संस्था में अपने स्तर से भी दर्ज कर सकेंगे। शासकीय शालाओं के अलावा अन्य सभी प्रबंधन की शालाएँ, जिनमें प्रायवेट स्कूल, मदरसा, केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय आदि को उनकी शाला के यूडीआईएसई कोर्ट के माध्यम से लॉग इन कर संबंधित शाला के प्राचार्य द्वारा शाला के समस्त विद्यार्थियों का प्रवेश, पोर्टल पर किया जायेगा।

शैक्षणिक वर्ष के 2 माह के भीतर ड्रॉप-आउट की पहचान करना, जिनमें ऐसे छात्र, जिनकी पदोन्नति या प्रवेश की सूचना अगले शैक्षणिक वर्ष में नहीं दी गयी है, उनकी पहचान कर उनका प्रवेश कराने की व्यवस्था की जायेगी। एजुकेशन पोर्टल-3.0 पर सभी शासकीय और प्रायवेट स्कूलों के लिये सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही हैं। इसमें सभी बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड, सीबीएसई, मदरसा बोर्ड और संस्कृत बोर्ड के अंतर्गत संचालित शालाएँ, केन्द्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय भी पंजीकृत हैं।

भोपाल में ट्यूबवेल खनन पर रोक

तेज गर्मी-गिरते भूजल स्तर को देखते हुए फैसला, उल्लंघन पर 2 साल तक की सजा

भोपाल (नप्र)। भोपाल में गर्मी और गिरते भूजल स्तर को देखते हुए ट्यूबवेल खनन पर रोक लगा दी गई है। अब कोई भी व्यक्ति 30 जून तक भोपाल जिले में ट्यूबवेल नहीं खुदवा सकेगा। इस संबंध में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सोमवार को आदेश जारी किया।

मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम की धारा 6(1) के तहत पूरे जिले में निजी नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है। सोमवार को हुई समयावधि (टीएल) बैठक में सभी एसडीएम ने भूजल स्तर के तेजी से गिरने और भविष्य में पेयजल संकट की आशंका जताई थी। इसके बाद कलेक्टर ने यह निर्णय लिया।

आदेश के मुताबिक, एसडीएम की अनुमति के बिना जिले में बोरिंग मशीनों का प्रवेश और खनन दोनों प्रतिबंधित रहेगा। केवल सार्वजनिक सड़कों से गुजरने वाली मशीनों को छूट दी गई है।

अवैध बोरिंग पर एफआईआर, 2 साल तक की सजा भी- अगर कोई मशीन अवैध रूप से जिले में प्रवेश करती है या नलकूप खनन करती है, तो संबंधित एसडीएम और पुलिस अधिकारी मशीन को जब्त कर एफआईआर दर्ज करवा सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर दो हजार रुपए जुर्माना, दो साल की सजा या दोनों हो सकते हैं।

शासकीय योजनाओं पर रोक नहीं- यह आदेश केवल निजी नलकूपों पर लागू होगा। शासकीय योजनाओं के तहत किए जा रहे नलकूप खनन कार्यों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। पीएचई द्वारा संचालित कार्यों को अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

पेयजल संकट से बचाव के लिए यह कदम- भोपाल जिले में कृषि और व्यवसायिक कार्यों के लिए भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है, जिससे जल स्तर तेजी से गिरा है। आने वाले ग्रीष्मकाल में संभावित पेयजल संकट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अगर निजी नलकूप खनन पर रोक नहीं लगाई जाती, तो जिले में गंभीर जल संकट की स्थिति बन सकती है।

बाबा बागेश्वर बने क्रिकेट मैच के हीरो

मुंबई में धीरेंद्र शास्त्री ने 4 विकेट लेकर महाराष्ट्र पुलिस को हराया; 38 रन की साझेदारी की

मुंबई/खजुराहो (नप्र)। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री 12 दिन की यात्रा पर मुंबई में हैं। यहां उन्होंने क्रिकेट में हाथ आजमाया। रविवार रात को कथा के बाद सेवादारों और अपनी सुरक्षा में तैनात महाराष्ट्र पुलिस के जवानों के साथ क्रिकेट मैच खेला। इसका वीडियो भी सामने आया है।

पं. धीरेंद्र शास्त्री और मुंबई पुलिस की टीम के बीच 6 ओवर का मुकाबला था। दोनों टीमों से 9-9 खिलाड़ी शामिल हुए। एक टीम में महाराष्ट्र पुलिस और निवासी सेवादार थे। दूसरी टीम में बाबा बागेश्वर, उनके सुरक्षाकर्मी और सेवादार शामिल थे।

पं. धीरेंद्र शास्त्री ने पहले ओवर में लिया विकेट

पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई टीम ने 6 ओवर में 48 रन बनाए। पं. धीरेंद्र शास्त्री ने पहले ओवर में 9 रन देकर एक विकेट लिया। चौथे ओवर में उन्होंने महज 3 रन देकर 3 विकेट झटके।

सेवादार के साथ की 38 रनों की पार्टनरशिप

लक्ष्य का पीछा करते हुए धीरेंद्र शास्त्री और सेवादार सत्यम शुक्ला ने पारी की शुरुआत की। दोनों ने 38 रनों की साझेदारी की। पांचवें ओवर की आखिरी गेंद पर पं. धीरेंद्र रन आउट हो गए। इसके बाद सुरक्षाकर्मी दीपेश सोनी ने आकर आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर टीम को जीत दिलाई। बागेश्वर पीठाधीश की टीम ने 9 विकेट से मुकाबला जीता।

इंदौर में भी क्रिकेट खेलते हुए वायरल हुआ था वीडियो

पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पहले भी कई मौकों पर क्रिकेट खेलते नजर आए हैं। तकरीबन 11 महीने पहले इंदौर में धीरेंद्र शास्त्री का बॉलिंग करते हुए एक वीडियो सामने आया था। जिसमें वो गेंदबाजी करते हुए नजर आए थे।

॥ मंदिरम् ॥

77

श्री रामलिंगेश्वर मंदिर, तेलंगाना

हैदराबाद से लगभग 70 किलोमीटर दूर संगारेड्डी के पास स्थित श्री रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर, नंदीकांडी भगवान शिव को समर्पित है और यह एक प्राचीन मंदिर है जिसे 10वीं/11वीं शताब्दी में कल्याण चालुक्यों द्वारा बनवाया गया था। मुख्य मंदिर तारे के आकार का है और इसमें एक शिव लिंग और एक स्पतिका लिंग भी है। मुख्य मंदिर (गर्भगृह) के सामने कछुए की एक छोटी मूर्ति है। स्तंभों पर वास्तुकला मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। यहाँ एक ध्वज स्तंभ है जो बहुत पुराना है और एक छोटा स्तंभ है जिस पर कुछ शिलालेख लिखे हुए हैं। मुख्य प्रवेश द्वार या थोरानम में नीचे की ओर इशारा करते हुए 7 कमल की पंखुड़ियाँ हैं और उनके बीच के 6 छेद 6 ऋतुओं (ऋतुओं) का प्रतिनिधित्व करते हैं और सूर्योदय के समय सूर्य की रोशनी प्रत्येक छेद के माध्यम से सीधे शिव लिंग पर पड़ती है और एक शानदार दृश्य बनाती है। इसके एक तरफ नटराज की मूर्तियाँ हैं और दूसरी तरफ शीर्ष पर पत्थर पर गजलक्ष्मी की मूर्तियाँ हैं।

मप्र में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने पर रोक नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया ; याचिका की खारिज

भोपाल (नप्र)। कमलनाथ सरकार द्वारा साल 2019 में ओबीसी वर्ग को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई विशेष अनुमति याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर कोई रोक नहीं हैं।

यूथ फॉर इक्वेलिटीसंगठन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह एसएलपी दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मप्र हाईकोर्ट के आदेश को सही मानते हुए स्पष्ट किया कि 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लागू करने में कोई न्यायिक अड़चन नहीं हैं।

कुशवाहा बोले- सरकार ने कोर्ट में मजबूती से पक्ष नहीं रखा

धर्मेंद्र कुशवाहा ने कहा- आज हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष नहीं रखा गया। इससे जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश की सरकार पिछड़े वर्ग को उनका अधिकार देना नहीं चाहती। ऐसी दशा में ओबीसी महासभा ने अपने वर्ग को न्याय दिलाने के लिए संगठन की ओर से अपने वर्ग से एक-एक रुपए इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट में अपने वकीलों से पैरवी कराई। जिसके कारण आज यूथ फॉर इक्वेलिटी संगठन की याचिका खारिज हुई

एमपी हाईकोर्ट ने कहा था- 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण में कोई अड़चन नहीं

महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य और एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा ने बताया कि 26 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैथ और न्यायाधीश विवेक जैन की संयुक्त बेंच ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के कानून का पालन करने का आदेश देते हुए कहा था कि 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। ऐसे में याचिका आज तक किस प्रकार से चल रही है। इसको देखते हुए हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की थी। उस आदेश के खिलाफ यूथ फॉर इक्वेलिटी संगठन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में एसएलपी दायर की गई थी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 8 में न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने 22वें नंबर पर इस एसएलपी की सुनवाई की। ओबीसी महासभा की ओर से एडवोकेट वरुण ठाकुर एवं एडवोकेट रामकरण के माध्यम से न्यायालय के सामने पक्ष रखा गया।

एमपी में 4500 सहकारी समितियों के चुनाव का कार्यक्रम जारी

1 मई से सितंबर के बीच 5 फेज में इलेक्शन

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में एक मई से सितंबर के बीच पांच चरणों में सहकारी समितियों के चुनाव कराए जाएंगे। राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी एमबी ओझा ने 4500 सहकारी समितियों के चुनावों का शेड्यूल जारी किया है। भले ही सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी ने सहकारी समितियों के चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया हो लेकिन, भाजपा और कांग्रेस के सहकारी नेताओं को इस बात का भरोसा नहीं हैं कि सरकार वास्तव में चुनाव कराएगी।

कांग्रेस विधायक बोले- चुनाव की सरकार की मंशा नहीं- अपेक्स बैंक के पूर्व अध्यक्ष और बदनावर से कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत कहते हैं- भाजपा सरकार की मंशा चुनाव कराने की है ही नहीं। करीब 17-18 सालों से को-ऑपरेटिव के चुनाव नहीं हुए। बीज निगम जब से बना तब से अब तक चुनाव नहीं कराया। मंडी समितियों के चुनाव नहीं करा रहे। अभी हाल ही में सरकार ने सहकारिता के कानून में संशोधन कर दिया है कि प्रशासक अनंत काल तक रह सकता है।हमने विधानसभा में इस मामले को उठाया और हाईकोर्ट को भी जब ये समझ आ गया तो सरकार को दबाव में चुनाव कार्यक्रम जारी करना पड़ा। हमें अब भी भरोसा नहीं कि सरकार वास्तव में चुनाव कराएगी।

बीजेपी से जुड़े नेताओं को भी चुनाव पर संदेह

जबलपुर जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष और सहकार भारती के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नारायण सिंह कहते हैं- ये चुनाव कार्यक्रम का पत्र हाईकोर्ट में सरकार को बचाने के लिए जारी किया है। सहकारिता के चुनाव होंगे इस पर संदेह है। उन्होंने कहा-ऐसे पत्र पहले भी तीन-चार बार निकाले जा चुके हैं। अभी हाल ही में हाईकोर्ट ने सरकार पर सहकारिता के चुनाव न कराने को लेकर 20 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई है। कोर्ट ने पूछा है कि आखिर चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं?

पांच चरणों में चुनाव कराने का फैसला

सहकारी समितियों के चुनावों के लिए हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने अब चुनाव कार्यक्रम जारी किया है। महाधिवक्ता कार्यालय ने इन चुनावों को अति आवश्यक बताते हुए पांच चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया है। समितियों के बाद जिला सहकारी बैंक और अपेक्स बैंक के संचालक मंडल के चुनाव भी कराए जाएंगे। हाल ही में विधानसभा के बजट सत्र में मप्र सरकार ने सहकारी अधिनियम में संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद यह पहला चुनाव होगा।

2013 से नहीं हुए चुनाव, 5 साल में कराना जरूरी है

प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के चुनाव आखिरी बार 2013 में हुए थे। इन समितियों का कार्यकाल 2018 में खत्म हो चुका है। कार्यकाल खत्म होने के छह महीने पहले ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। चुनाव न होने की स्थिति में अधिकतम छह महीने तक कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। लेकिन, करीब तीन सालों से चुनाव टलते जा रहे हैं। सहकारी समितियों में प्रशासकों के भरोसे काम चल रहा है।

चुनाव न होने से असंतोष बढ़ा, हाईकोर्ट में लगीं याचिकाएं- को-ऑपरेटिव चुनाव न होने से असंतोष बढ़ा और जबलपुर हाईकोर्ट के साथ ग्वालियर खंडपीठ में कई याचिकाएं दायर हुईं। मार्च में महाधिवक्ता कार्यालय ने सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव और सहकारिता विभाग को सुझाव दिया कि चुनाव जल्द कराना जरूरी है।

7 हार्ट पेशेंट की मौत के आरोपी डॉक्टर पर एफआईआर

खुद को लंदन का बताकर दमोह में किए थे 15 ऑपरेशन

भोपाल/ दमोह (नप्र)। दमोह के मिशन अस्पताल में हार्ट सर्जरी के बाद जिन सात मरीजों की मौत का दावा किया जा रहा है, उनमें से पांच की पहचान हो गई है। मामले में आरोपी डॉ. नरेंद्र यादव उर्फ नरेंद्र जॉन केम के खिलाफ

कोतवाली में रविवार देर रात एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें दो अन्य को भी आरोपी बनाया गया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) मुकेश जैन ने ये एफआईआर कराई है। उन्होंने पांचों मरीजों के परिजन को पत्र लिखकर बयान देने के लिए बुलाया है। मामले की जांच करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम दमोह पहुंची है। इसमें रिंकल कुमार, ब्रजवीर कुमार, राजेंद्र सिंह शामिल हैं। टीम मृतकों के परिजन के बयान दर्ज करेगी।

इससे पहले मामले की जांच टीम में सीएमएचओ अशोक जैन के अलावा जिला अस्पताल के डॉ. विशाल शुक्ला और डॉ. विक्रांत चौहान शामिल थे। जांच में मरीजों की मृत्यु एन्जियोग्राफी और एन्जियोप्लास्टी की वजह से होना पाया गया है।

15 ऑपरेशन किए, 7 मरीजों की मौत का आरोप- मिशन अस्पताल पर इससे पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग और धर्मांतरण का आरोप भी लग चुका है। अब दावा है कि यहां डॉ. नरेंद्र यादव उर्फ नरेंद्र जॉन केम नाम के शख्स ने लंदन के कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. एनजोन केम के नाम से प्रैक्टिस की। 15 हार्ट ऑपरेशन भी किए। इनमें से 7 मरीजों की मौत हो गई। पूछताछ शुरू होते ही खुद को कार्डियोलॉजिस्ट बताने वाला डॉ. नरेंद्र यादव उर्फ नरेंद्र जॉन केम भाग निकला। मामला 4 अप्रैल को सामने आया, जब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की। इसमें मिशन अस्पताल में 7 हार्ट पेशेंट्स की मौत और फर्जी डॉक्टर का जिक्र किया।

छिंदवाड़ा में दो कारें टकराईं, 3 की मौत

मृतकों में 8 महीने की बच्ची भी शामिल ; कार काटकर निकाले शव, 5 गंभीर

छिंदवाड़ा (नप्र)। छिंदवाड़ा में दो कारों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार को काटकर शव निकालने पड़े।

घटना सोमवार दोपहर करीब 3.30 बजे कुंडीपुरा थाना क्षेत्र के घाट परासिया की है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। छिंदवाड़ा सीएसपी अजय राणा ने बताया कि हादसे में एक बच्चे, महिला समेत 3 लोगों की मौत हुई है।

हादसे में पिता-बेटी की मौत- परिचित सज्जू सूर्यवंशी ने बताया कि दिनेश उईके (32) कपुरदा माता मंदिर दर्शन के लिए परिवार के साथ जाने वाले थे। इसलिए रविवार रात को उन्होंने पड़ोसी से कार ली थी। वह पत्नी कंचन उईके, 8 महीने की बेटी और कंचन की बुआ की बेटी के साथ सुबह मंदिर रवाना हुए थे।

छिंदवाड़ा से 17 किमी दूर घाट परासिया के पास सामने से आ रही महाराष्ट्र पासिंग गाड़ी से टक्कर से हो गई। टक्कर में दिनेश ने मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, बेटी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। कंचन और उसकी बुआ की बेटी की हालत गंभीर है, उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।

सज्जू ने बताया कि दिनेश परिवार के साथ बाहर से आकर छिंदवाड़ा के रोहना खेह गुरैया में रह रहा था। जायसवाल पोल्ट्री फॉर्म में काम करता था। पुलिस का कहना है कि छिंदवाड़ा के रहने वाले दिनेश और महाराष्ट्र के निवासी की आपस में गाड़ियां भिड़ीं है। दोनों के परिवार अभी नहीं आए हैं। उनके बारे में जानकारी सूचना दी जा रही है।

घायल बोला- मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे

घायल धीरज ढोके ने बताया कि वह नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। वह सोमवार को कार से कपुरदा मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। इस दौरान सामने से आ रही कार से उनकी टक्कर हो गई। उनकी कार में 3 लोग थे।

इटारसी में बस पलटी, महिला समेत 2 की मौत

10 से ज्यादा यात्री घायल ; पथरोटा पुलिया के पास गाड़ी बेकाबू हुई

इटारसी (नप्र)। इटारसी में ऑर्डनेंस फैक्ट्री की ओर से आ रही बस पथरोटा पुलिया के पास सोमवार दोपहर 12.30 बजे पलट गई। हादसे में बस कंडक्टर नरेंद्र पिता महेंद्र सिंह चौहान (40) निवासी न्यू यार्ड और महिला यात्री नजमा खातून (45) निवासी पांडरी की मौत

हुई है। एसडीओपी वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि हादसे में 8 से 10 यात्री घायल हुए हैं। इनमें इटारसी कॉलेज में परीक्षा देने जा रही मनीषा की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायल यात्रियों को इटारसी के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।घायल यात्री रीना और शांति राठौड़ ने बताया कि वे भोपाल इलाज कराने के लिए जा रहीं थी। बस पथरोटा के पुराने पंजाब नेशनल बैंक की पुलिया के पास बेकाबू होकर पुराने पलट गई। हादसे के बाद इटारसी एसडीएम टी प्रतीक राव घायलों को देखने श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल पहुंचे।

चयनित अधिकारी सेवा भाव और सकारात्मक मानसिकता के साथ करें अपने अधिकारों का उपयोग : सीएम यादव

मुख्यमंत्री ने राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के 118वें संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया शुभारंभ

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय समाज स्व-नियंत्रित और सुसंस्कृत समाज है। राज्य सेवा के लिए चयनित अधिकारी पवित्र सेवा भाव और परिष्कृत मन मस्तिष्क के साथ, उन्हें मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए अपने दायित्व निर्वहन की ओर अग्रसर हों। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रशिक्षु अधिकारियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अधिकारी अपनी कुशलता और दक्षता से सभी की आशाओं-आकांक्षाओं पर खरे उतरें यही कामना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के 118वें संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ सत्र को प्रशासन अकादमी में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का महानिदेशक प्रशासन अकादमी श्री सचिन सिन्हा द्वारा पुष्प-गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। प्रशिक्षण शुभारंभ पर अकादमी संकल्प गान की प्रस्तुति हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के साथ प्रशिक्षु अधिकारियों का ग्रुप फोटो भी हुआ।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रशिक्षुओं से कहा कि नर्सरी कक्षा से लेकर अब तक के शिक्षण-प्रशिक्षण से मिले ज्ञान के आत्म अवलोकन से अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों और कार्यों को दक्षतापूर्वक संपन्न करें। उन्होंने कहा कि शिक्षण से व्यक्ति और प्रशिक्षण से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हमारी पाठ्य पुस्तकें अपार ज्ञान का भंडार हैं, लेकिन दायित्वों को पूरा करने के लिए इसी ज्ञान

की मदद से अपना मार्ग स्वयं खोजना होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने दायित्वों के निर्वहन में पारिवारिक मूल्यों का ध्यान रखने, जनसामान्य के साथ शालीन व्यवहार और संवाद क्षमता विकसित करने तथा आउट ऑफ बॉक्स सोचते हुए समाज हित में नवाचार करने के लिए प्रेरित किया। बड़े पद की जिम्मेदारी के साथ-साथ परिवारजन और मित्रों की अपेक्षाओं पर बने रहना भी एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि आपका व्यवहार ऐसा हो कि आप अधिक से अधिक लोगों की आशाओं व आकांक्षाओं पर खरे उतर सकें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में मिशन कर्मयोगी से विकास और जनकल्याण की दिशा में राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्यरत है। चयनित अधिकारियों को स्वयं के परिश्रम और ईश्वर की कृपा से जनसेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने सबसे अपेक्षा की कि प्रशिक्षण उपरांत अधिकारी, मैदानी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आत्मविश्वास और सकारात्मक मानसिकता के साथ सुशासन और गुणवत्तापूर्ण लोक सेवाओं के लिए उत्तरदायी-जवाबदेह-पारदर्शी-स्वच्छ और संवेदनशील भूमिका का निर्वहन करें।

शुभारंभ सत्र को अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री संजय दुबे, महानिदेशक प्रशासन अकादमी श्री सचिन सिन्हा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री राजा बाबू सिंह ने भी संबोधित किया। संचालक प्रशासन अकादमी श्री मुजीबुर्रहमान खान ने आभार माना। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा में चयनित वर्ष 2020 और 2021 बैच के उप जिलाधीश, उप पुलिस अधीक्षक और नायब तहसीलदार पद के लिए चयनित कुल 83 प्रशिक्षुओं के सात सप्ताह का संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम 7 अप्रैल से 23 मई 2025 तक प्रशासन अकादमी में संचालित होगा।

मध्यप्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव-2025 का आयोजन 27 अप्रैल को इंदौर में

भोपाल (नप्र)। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित मध्यप्रदेश 'टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव-2025' का आयोजन 27 अप्रैल को इंदौर में किया जाएगा। यह ऐतिहासिक सम्मेलन राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) 2025 में की गई निवेश प्रतिबद्धताओं को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में इस आयोजन में राज्य की प्रौद्योगिकी नेतृत्व की दिशा में रोडमेप प्रस्तुत किया जायेगा। आईटी एवं संबंधित क्षेत्रों में राज्य सरकार के निवेश कार्यान्वयन नीति को गति देने और राज्य को एक प्रमुख प्रौद्योगिकी गंतव्य के रूप में उभारने के लिये यह आयोजन महत्वपूर्ण होगा। यह निवेश प्रगति को ट्रेक पर लाने, नीतिगत निर्णयों को सामने लाने और सहयोग बढ़ाने के लिये एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा।

वीडी को मिलता जीवनदान !

मध्य प्रदेश भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा ? इसको लेकर जिन नामों की चर्चा जोरों पर थी अब वह पूरी तरह पीछे रह गये है। सीएम की तरह नया नाम प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का सामने आए तो उसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सूत्र बताते हैं कि सत्ता और संगठन में समन्वय के अभाव में नए प्रदेश

मोहन का मंत्रालय

आशीष चौधरी

अध्यक्ष की घोषणा टलती जा रही है। इसी का फायदा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा को जीवन दान के रूप में मिल रहा है। केंद्रीय नेतृत्व से संपर्क रखने वाले सूत्र बताते हैं कि मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है इसलिए अभी तक किसी नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। इसलिए सारा दारोमदार केंद्रीय नेतृत्व पर सौंप दिया गया और मध्य प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष नाम भी हैरान करने वाला होगा तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

साहब की मैडम का हंगामा ?

प्रदेश में महिलाओं द्वारा प्रताड़ित पतियों के किस्से आए दिन सामने आते रहते हैं और बेचारे पति, अत्याचार सहन भी कर रहे हैं लेकिन एक आईएएस अफसर को भी ऐसी परिस्थितियों से दो-चार होना पड़ रहा है। प्रदेश के एक महत्वपूर्ण जिले के प्रशासनिक मुखिया की मैडम का हंगामा मंत्रालय तक पहुंच गया है। सूत्र बताते हैं कि मैडम का हंगामा पिछले दिनों काफी चर्चाओं में रहा जब मैडम में जोर-जोर से मोहल्ला सर पर उठा लिया। सूत्र बताते हैं कि मैडम को शांत करने के लिए स्थानीय पुलिस के जब बस की बात नहीं रही तो जिले के पुलिस अधीक्षक साहब मौके पर पहुंचे और किसी तरह मामला शांत कराया। सूत्र बताते हैं कि मैडम आए दिन इसी तरह हंगामा करती है और परेशान पुलिस को होना पड़ता है। पुलिस अधीक्षक में मीडिया कर्मियों को पारिवारिक मसला बात कर पल्ला झाड़ लिया।

शराबबंदी फायदा किसको

प्रदेश के पवित्र नगरों में शराब बंदी के मोहन सरकार के निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए। इस निर्णय से पवित्र नगरों का और आदर भाव और स्वस्थ वातावरण निर्मित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इस निर्णय से शराब माफिया का एक सिंडिकेट काफी खुश है। सिंडिकेट का मानना है पवित्र नगरों में शराब बंदी से उनको नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही होगा। सिंडिकेट अब खुले आम अवैध शराब की बिक्री अधिक दरों पर करेगा और मोटा मुनाफा भी कमायेगा। यह सर्व ज्ञात है कि शराब के सिंडिकेट न केवल स्थानीय पुलिस को बल्कि आबकारी के स्थानीय अमले को भी सेट करके अवैध शराब का बड़े स्तर पर कारोबार करते हैं। सरकार के निर्णय से सिंडिकेट को 500 करोड़ रुपये से अधिक के मुनाफे की संभावना है जबकि सरकार को इतने ही घाटे का अनुमान है। बता दे कि यह सिंडिकेट पार्टी से जुड़ा हुआ है।

उच्च नौकरशाही पर मेहरबानी क्यों ?

आजीविका मिशन में नियुक्तियां को लेकर वहां के पूर्व संचालक आईएफएस के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज हो गई है। मामले में कुछ अधिकारियों के भी नाम है जिन्होंने अवैध नियुक्तियों में शीर्ष अधिकारियों के निर्देशों का पालन किया। पुलिस ने यह एफ़आईआर सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर की है। सूत्र बताते हैं कि एक सदस्य समिति ने आजीविका मिशन में नियुक्तियों को लेकर पूर्व उच्च नौकरशाहों पर भी उंगली उठाई थी और यहां तक रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि इन नियुक्तियों में पूर्व नौकरशाहों का भी हाथ है लेकिन पुलिस ने केवल आईएफएस अधिकारी को ही कानून के शिकंजे में क्यों लिया यह चर्चा का विषय है?

.....तो निकलेंगे कई सौरभ

मध्य प्रदेश के आईएएस अफसरो की संपत्ति पिछले दिनों सार्वजनिक हुई। संपत्ति के विवरण को सार्वजनिक होने पर जहां आईएएस अधिकारी अपनी निजात से जोड़कर देख रहे हैं। वही उनका कहना है कि संपत्ति सार्वजनिक रूप से उजागर होने से कहीं मुश्किलें खड़ी न हो जाए। इसके उलट एक आईएएस लॉबी का यह भी कहना है कि अधिकारियों ने संपत्ति की घोषणा की यह तो नमूना मात्र है लेकिन अधिकारियों की बेनामी संपत्तियों का सच सामने आएगा तो कई सौरव शर्मा निकलेंगे ?